

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 मार्च, 1983

खंड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 10 मार्च, 1983

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एव उत्तर	(4)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(4)19

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)23
प्वायंट आफ आर्डर –	
क्षेत्रीय तथा जल विवाद सम्बन्धी रैज्योलूशन को अस्वीकार करने सम्बन्धी	(4)28
विभिन्न विषयों का उठाया जाना–	
(i) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल अध्यापकों की मांगों सम्बन्धी	(4)30
(ii) कोसली में किसानों के सम्मेलन में नुकसान पहुंचाने सम्बन्धी	(4)32
(iii) अम्बाला भाहर में गुरुद्वारा मंजी साहब को घेरा डालने तथा वहां पर तनाव होने सम्बन्धी	(4)32
(iv) मुख्य मंत्री के भाई द्वारा कथित जमीन हड़पने सम्बन्धी	(4)33
प्वायंट आफ ओर्डर–	
श्री किताब सिंह एम0एल0ए0 की कथित अवैध गिरफ्तारी आदि के तथ्य की तहकीकात करने के लिए सदन की एक समिति की नियुक्ति का सुझाव	(4)34
वक्तव्य	

राजस्व मंत्री द्वारा सूखे तथा ओलावृष्टि के कारण हुई हानि के लिए मुआवजा देने सम्बन्धी	(4)38
प्वायंट आफ ओर्डर-	
श्री किताब सिंह एम0एल0ए0 की कथित अवैध गिरफ्तारी आदि के तथ्य की तहकीकात करने के लिए सदन की एक समिति की नियुक्ति का सुझाव	(4)39
वक्तव्य	
राजस्व मंत्री द्वारा सूखे तथा ओलावृष्टि के कारण हुई हानि के लिए मुआवजा देने सम्बन्धी (पुनरारम्भ)	(4)40
सस्पेंशन आफ सिटिंग	(4)41
वक्तव्य	
राजस्व मंत्री द्वारा सूखे तथा ओलावृष्टि के कारण हुई हानि के लिए मुआवजा देने सम्बन्धी (पुनरारम्भ)	(4)42
गैर सरकारी संकल्प	
जिला अम्बाला की तहसील अम्बाला को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने सम्बन्धी	(4)47

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 10 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारासिंह) ने अध्यक्षता की।

तांराकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सवाल होंगे।

Coal received in the State

***83. Smt. Chandrawat:** Will the Minister for food and Supplies be pleased to state the total quantity of coal (in tons) of different qualities received, separately, in the State during the years 1979-80, 1980-81 and 1981-82 separately togetherwith the criteria adopted for its distribution in the State?

Industries Minister(Shri Lachhman Singh): Under the Haryana Coal Control Order, 1977 the food and Supplier Department deal with Slack Coal for brick kiln industry and Soft Coke for domestic consumption. The total Quantity for Slack Coal and soft coke received in the State during the years 1979-80, 1980-81 and 1981-82 is given below:-

(Figures in tones)			
	1979-80	1980-81	1981-82
Stack Coal	17,415.4	1,60,873.7	1,29,871.0
Soft Coke	24,600.0	14,280.7	12,040.0

There is no control on the price and distribution of slack coal. So far as soft coke is concerned, it is being distributed by the district authorities on the rates fixed by the District Magistrates against Distribution cards, subject to the availability of stocks.

श्रीमति चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैंने सवाल यह पूछा था कि कोयले की डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्रिटेरिया है लेकिन उसका जवाब मुझे नहीं मिला। मैंने सारी किस्म के कोयले के बारे में पूछा था कि किस प्रकार से कन्जूमर्ज और दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है।

श्री लछमन सिंह: साफ्ट कोक चालीस किलोग्राम एकराशन कार्ड पर महीने में दिया जाता है। जो कोयला कानफेड के थ्रू यानि बाई रेल आता है वह सस्ता होता है। लेकिन जो कोयला प्राइवेट डीलर्ज बाई रोड लाते हैं उसका रेट ज्यादा होता है, क्योंकि बाई रोड आने पर किराया ज्यादा खर्च होता है। साफ्ट कोक का होलसेल रेट 226.02 रुपये पर टन है। इसमें रेलवे किराया और टैक्स लगता है। हिसार और पानीपत के अन्दर

हमारे कोल डम्पस में यह कोयला आता है और कान्फेड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हरियाणा राज्य का साफ्ट कोक का मासिक आबंटन 1000 गाड़िया हैं। जहां तक स्लैक कोक का सम्बन्ध है इसकी डिस्ट्रीब्यू इन पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। जिस आदमी के पास स्टेट और सैन्ट्रल सेल्ज टैक्स का नम्बर है और सिविल सप्लाइ डिपार्टमेंट से लाइसेंस ले रखा है, वह ला सकता है। जितने भी वह रैक्स अप्लाइ करता है, वह उसे दे दिये जाते हैं लेकिन उसे अपना नाम बंगाल, बिहार और आसाम रेलवे में रजिस्टर कराना पड़ता है उसकी डिस्ट्रीब्यू इन पर कंट्रोल नहीं है क्योंकि सन् 1977 में जनता गवर्नमेंट के टाइम पर स्लैक कोयले पर जो पाबन्दी थी वह बिदड़ा कर ली गई है।

श्री मंगल सैन: मंत्री महोदय ने सन् 1979-80, 1980-81 और 1981-82 की कोयले की फिगरज दी है कि इतना इतना आया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट की और से ऐलोके इन कितनी हुई थी और कितना आया है?

श्री लछमन सिंह: सैन्ट्रल गवर्नमेंट की और से ऐलाके इन कोई नहीं होती। ऐलाके इन बी0सी0एल0 ओर सी0सी0एल करती हैं। हमें केवल स्पान्सर रिप की पावर है। साफ्ट कोक के पहले 41 रैक्स स्पान्सर कर सकते थे लेकिन अब 20 कर दिये हैं क्योंकि अब वैगन अवेलेबल नहीं हैं। अगर महीने में 20 वगनज आ जायें तो साल में 240 हो जाते हैं। वह आने पर डिपैन्ड करता है। अप्रैल 1980 में सिर्फ एक रैक आया था और

जनवरी, 1981 में भी सिर्फ एक रैक आया। फरवरी, 1981 में फिर पांच रैक्स आये। 30-09-82 तक 13 रैक्स आ चुके हैं और अभी और भी आ रहे हैं। जहां तक स्लेक कोल का सम्बन्ध है आसान कोल फील्ड से 78 रैक्स और बंगाल बिहार कोल फील्ड से 81 रैक्स आये।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अगर मंत्री महोदय यह अनुभव करते हैं कि आसाम और बंगाल से कम रैक्स आते हैं और उसकी डिस्ट्रीक्यूशन गवर्नमेंट आफ इंडिया करती है तो क्या उनसे ज्यादा रैक्स लेने की कोशिश की है?

श्री लछमन सिंह: डाक्टर साहब ऐलोकेशन तो कोल फील्ड वाले करते हैं। हम केवल स्पॉन्सरप करते हैं कि इसे इतने रैक्स कोयला दे दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : इनका सवाल यह है कि क्या आपने गवर्नमेंट आफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कि कोयला कम मिला है।

श्री लछमन सिंह: रिप्रेजेंट तो बहुत बार किया है और सरकार की ओर से तौ बार-बार कोशिश होती रहती है कि अधिक कोयले के रैक्स मिलें।

श्री वीनेन्द्र सिंह: क्या मंत्री जी बताएंगे कि कोयले की भार्टेज को पूरा करने के लिये जितने रैक्स हमें चाहिए, उतने आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं?

श्री लछमन सिंह: कोयले की कोई भार्टेज नहीं है। यह आप इस बात से अन्दाजा लगा सकते हैं कि तीन-चार महीने पहले ईंटों का रेट काफी ज्यादा था लेकिन अब रेट काफी घटा है कोयले की कोई भार्टेज नहीं है। कोयला रैक्स से भी आता है और बाई रोड भी आता है। जनवरी 1980 में बाई रोड 80 हजारप टन कोयला आया है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मंत्री जी के नोटिस में डिपार्टमेंट की ओर से या डिप्टी कमि नर की ओर से भट्टे वालों की या छोटी इन्डस्ट्री वालों की िाकायत आई है कि कोयले की भार्टेज है?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, पिछले दिनों भट्टे वालों की ए गोसिये ान की मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें हमने कहा था कि आप अगर रैक्स लेने के लिए तैयार हैं, तो हम दे सकते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। एक रैक लेने पर 15-16 लाख रूपये खर्च होता है। आसाम के रैक पर 15-16 लाख रूपये खर्च होता है और बंगाल-बिहार के रैक पर 8-10 लाख रूपया खर्च होता है। उन्होंने रैक लेने के लिए बिल्कूल इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने पैसे क्यों डमप करें।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या आपके पास छोटी इन्डस्ट्री वालों की कोई री-प्रेजन्टे ान आयी है? सोनीपत, गुड़गांव और

जगाधारी के छोटी इन्डस्ट्री वालों ने िाकायत की हैं कि वे बड़े इन्डस्ट्रीयलिस्टस से कोयला ब्लैक में लेते हैं।

श्री लछमन सिंह: इन्डस्ट्री का कोयला सैपरेट हैं। उसका इस क्वै चन से कोई सम्बन्ध नहीं है। स्लेक कोयला भट्टों में इस्तेमाल होता है।

श्री अध्यक्ष: क्या आपके पास कोई िाकायत आई है?

श्री लछमन सिंह: वह िाकायत इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट में आई होगी।

श्रीमती चन्द्रावती: वह डिपार्टमेंट भी तो आपके पास ही है। क्या मंत्री महोदय यह अ योरेन्स देंगे कि अगर कोयले की भार्तेज के बारे में कोई िाकायत है तो उसे रफा करेंगे?

श्री लछमन सिंह: जरूर रफा करेंगे।

श्री भागीराम: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो फिगरज दी हैं उनसे यह पता चलता है कि 1979-80 में 24,600, 1980-81 में 14,280.7 और 1981-82 में 12,040 टन साफ्ट कोयला आया है जिसका मतलब यह है कि कोयले की अवेलेबिलिटी कम होती रही है। देा के अन्दर आज फयूल की कमी है फील हो रही है। चाहे गांव हो या छोटा कसबा हों, क्या मंत्री महोदय इस बात को अरेंजमेंट करेंगे कि बेाक राान कार्ड

के जरिये हरेक गांव में या हरेक टाउन में लोगों को कोयला मिल सके ।

श्री लछमन सिंह: सॉफ्ट कोक के लिए हमारी यह पालिसी हैं कि गांव के लोग भी अगर लेना चाहे तो कोई पाबन्दी नहीं हैं । जैसे मैंने अर्ज किया हैं कि हम यह कोयला कान्फैड के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं । रैक्स कान्फैड मंगाती हैं, क्योंकि उनके डम्पस बने हुए हैं । एक जगह पर तो इतना कोयला कन्ज्यूम नहीं हो सकता हैं और दूसरे अगर एक जगह पर रखेंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त कैरिज का खर्चा बहुत बढेगा । आप को पता हैं कि कई दफा रेलवे में वैगन्ज नहीं मिलते और कई दफा पिट्स में स्ट्राईक वगैरा होती हैं । सरकार की यह क्लयर नीति हैं कि जो भी यह कोयला लेना चाहे, ले सकता हैं । कई जगह पर लोग लेते भी हैं । उनको कोयला देने के लिए कोई बैन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: हर साल कोयले की अवेलेबिलिटी घट रही हैं, आपने इनके इस सवाल का जवाब नहीं दिया ।

श्री लछमन सिंह: कम होने का कारण यह है कि एक तो कोयला बाई रोड भी आ रहा हैं और दूसरे उसकी फ्री सेल पर कोई पाबन्दी नहीं हैं । इसके इलावा कोयला लाने के औरप भी चैनल्ज हैं । कहने का मतलब यह है कि आजकल कोयले की कोई दिक्कत नहीं ।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या यह सत्य है कि सरकार जानबूझ कर सस्ता कोयला ला रही है और इस वजह से पानीपत पावर हाउस भी खराब हो रहा है? (व्यवधान व भाोर)

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, इनके लिए तो सरकार कोयला लाती ही नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती: पब्लिक सैक्टर की जो कम्पनियां हैं यदि उनके लिये सरकार नहीं लाती है तो दूसरा कौन कोयला लाता है? क्या यह तथ्य नहीं है कि सरकार उनके लिए कोयला जानबूझकर सस्ता लाती है? (व्यवधान व भाोर)

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, हलांकि इसका मेन सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है फिर भी मैं इनको यह बता देता हूँ कि जी थर्मल का कोयला है, वह क्लास वन कोयला मिलता है और वह रानीगंज से मिलता है। किसी भी व्यापारी को उस कोयले की एलोके ान नहीं होती। थर्मल के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कुछ रिस्ट्रीक् ांज लगा रखी है। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: I think, he requires a separate notice.

Smt. Chandravati: I want to know about the supply of coal, Sir, and I think there is no need of a separate notice for that. (Interruptions.)

श्री रामबिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने जो बताया है उसके मुताबिक एक तरफ तो स्टेट में कोयले की कमी

नहीं है लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने यह बताया है कि 40 रैक्स की रिक्वायरमेंट के अगेन्स्ट सिर्फ 1 रैक ही मिला है, क्या यह दोनों बातें कान्फ़्लिक्टरी नहीं हैं?

श्री लखमन सिंह: यह तो बहुत पुरानी बात है। लगभग दो-तीन साल पहले की बात है।

श्री मंगल सैन: सर, इन्होंने 1980 की ही तो बात बतायी है।

श्री लखमन सिंह: सर, इस साल 13 रैक्स आ चुके हैं। इसके अलावा और अभी आ जायेंगे। बाई रोड आ जायेंगे। वहां से कुछ रैक्स चले हुए हैं। जैसे मैंने कहा है, अब कोयले की कमी नहीं है।

Grant to M.D. University, Rohtak

***81 Dr. Bhim Singh Dahiya:** Will the Minister of State for Education be pleased to state the total amount of grants, if any, paid to M.D. University, Rohtak since October, 1978 to date?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): केवल 10,71,36,480 रुपये।

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 10,71,36,480 रुपये की ग्रांट दी गई है, मैं इनसे यह जानना चाहता हूँ कि इसमें से कितना पैसा बिलडिंग

कंस्ट्रक्शन के लिए था औरप वह असलियत में खर्च हो गया है या नहीं?

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, जो पैसा नान-प्लान और प्लान साईड के लिए दिया गया है, उसका ब्यौरा मैं दहिया साहब की इन्फर्मेसन के लिए दे देता हूँ। 1977-78 में प्लान साईड पर 75 लाख रूपया, टोटल 2 करोड़ 85 लाख रूपया, 1980-81 में प्लान साईड पर 1 करोड़ 67 लाख 98 हजार और नान-प्लान साईड पर एक करोड़ 18 लाख, टोटल 2 करोड़ 85,98,000, 1981-82 में प्लान साईड पर 1 करोड़ 8 लाख रूपया और नान-प्लान साईड पर 1 करोड़ 29 लाख 38,480, टोटल 2 करोड़ 37 लाख 38,480 रूपया और 1982-83 में प्लान साईड पर 50 लाख रूपए और नान-प्लान साईड पर 1 करोड़ 38 लाख और टोटल 1 करोड़ 88 लाख रूपए और अब तक कुल 10 करोड़ 71,36,480 रूपए की ग्रान्ट दी गयी है। इसमें जो प्लान साईड पर खर्चा है, वह करीब-करीब सारा खर्च हो चुका है, बाकि पुरा ब्यौरा मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि सवाल में इस बारे में नहीं पूछा गया था।

श्री हीरा नन्द आर्य: मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहूंगा। जैसे कि प्रोसीजर बनाया हुआ है कि यूटिलाईजेसन सर्टीफिकेटस आने के बाद ही अगली ग्रान्ट रीलीज की जाती है, क्या यहां से भी यूटिलाईजेसन सर्टीफिकेटस आने के बाद ही

उनको अगली ग्रांटस दी गई हैं या पहले भी दे दी गयी है? इसके अलावा फर्नीचर पर कितना पैसा खर्च किया गया है?

श्री जगदी ा नेहरा: सर, फर्नीचर के बारे में मेरे पास डिटल्ज इस समय नहीं हैं। पैसे की यूटिलाईजे ान सर्टीफिकेटस के बारे में इनका सवाल नहीं था, इसलिए मैंने वह इन्फर्मे ान नहीं मंगवायसी और अमूमन यूनिवर्सिटी के लिए जिना भी बजट में प्लान साईड पर और नान-प्लान पर, प्रोविजन होता है, यह हर साल बढ़ता ही रहता है, लेकिन प्लान साईड वाला तो करीब-करीब खर्च हो जाता है।

श्री मंगल सैन: क्या ि ाक्षा मंत्री महोदय या मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई ि ाकायत इन वर्षों के दौरान यानी 179-80 या 1981-82 या उसके बाद तीन-चार वर्षों में जब से पैसा भुरु किया है सरकार के पास मिस-एप्रोप्रिए ान की या रौंग यूटिलाईजे ान की इम्प्रोपर यूटिलाईजे ान आफ फन्डज के बारे में कोई ि ाकायत प्राप्त हुई है? अगर मिली है तो उसके ऊपर क्या एक् ान लिया गया है?

श्री जगदी ा नेहरा: स्पीकर साहब, वैसे जो इसके बारे में सैपरेट क्वे ान देना चाहिए लेकिन अगर डाक्टर साहब स्पैसिफिकली यह बता दें कि किस टाईप की ि ाकायत के बारे में वह पूछना चाहते हैं। उसका जवाब मंगवा लिया जाएगा। ऐसे ही वेग ि ाकायत के बारे में कह सकता हूँ।

Shri Mangal Sein: I want to know whether you have received any complaint regarding mis-use or embezzlement of funds?

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, अगर उनके इल्म में न हो तो वह कैसे कहेंगे कि आयी है या नहीं आयी है।

Shri Mangal Sein: He has got the information, Sir. He Knows everything but he is hiding it from the House, Sir. (Interruptions)

श्री जगदी ा नेहरा: स्पीकर साहब, डाक्टर साहब, स्पैसिफिकली बतायें कि फलां चीज की एम्बैजलमेंट के बारे में पूछना चाहते हैं तो पता करके बता दिया जाएगा।

श्री मंगल सैन: आप बतायें कि क्या फर्नीचर के बारे में आपको कोई रिक्वायत मिली है?

श्री जगदी ा नेहरा: जैसे मैंने अर्ज किया, यह तो अलग सवाल है। इसके बारे में अलग से नोटिस दे तो इनफॉर्मेशन मंगायी जाएगी ऐसे कैसे इनको जवाब दिया जा सकता है?

Shri Mangal Sein: I seek your protection, Sir. We want information about 10 करोड़ रुपया जो दिया गया है। He knows the person, who is handling the affairs for the University.

श्री जगदी ा नेहरा: सर, मैं आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जितनी इन्होंने इन्फॉर्मेशन सवाल में पूछी थी,

वह दे दी गई हैं। अब यह फर्नीचर के बारे में विधायक की बात पूछते हैं, कितना खरीदा गया है तो उसके लिए इन्हे तो अलग से नोटिस देना पड़ेगा। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: आपके पास फर्नीचर के बारे में कोई कम्प्लेंट आयी है या नहीं? अगर आपके पास इन दो प्वांचटस के बारे में अब यह इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मंडे को यह इन्फॉर्मेशन दे दें। (व्यवधान व भाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जब हमने एक स्पैसिफिक सवाल पूछा है कि कितनी ग्रांट एक यूनिवर्सिटी को दी गई है तो ग्रांट कैसे युटिलाइज की गई है वा कैसे नहीं की गई है, इसके लिए भी तैयार हो कर नहीं आये। इसकी डिटेल्स तो मंत्री महोदय के पास होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मैंने इनको दो सवालों के लिए टाइम दे दिया है। उनका जवाब आ जायेगा।

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने दस करोड़ 71 लाख 36,480 रुपये की ब्रेक-अप बताई है जो ग्रांट यूनिवर्सिटी को दी गई है। इसमें एक बात साफ जाहिर है कि ज्यादातर पैसा बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन के लिए प्लान साइड पर था। आज तक कोई भी बिल्डिंग, एक बिल्डिंग, को छोड़ कर नहीं बनाई गई है। जो एक बन गई है वह भी गलती से जब कोई दूसरा आफिसियेटिंग बार्डर्स चान्सलर था तब बन गई थी उस वक्त

होस्टल की बिल्डिंग बनी थी। वरना हर साल बिल्डिंग मैटीरियल खरीदा जाता है। मैं एक स्पैसिफिक इनटॉस भी दे दूँ जो ये पूछना चाहते थे, सन 1979 में 40 टन लोहे के बारे में यह कहा गया कि यह चोरी हो गया है। सिमेंट और लोहा 50-60 लाख या एक करोड़ रुपये का हर साल खरीदा जाता है जो वहाँ पर चोरी होने लग रहा है और पैसा बैकार में खर्च हो रहा है, क्योंकि जो साहब आज वहाँ पर बैठे हुए हैं वह साईंउ या बिल्डिंग का फैसला नहीं हाने देते और जिसकी वजह से उसकी प्लान नहीं बनती। इसलिए हर साल कहा जाता है कि इतना सीमेंट खराब हो गया या लोहा चोरी हो गया। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या राइटिंग में कोई कम्प्लेंट आई थी कि 40 टन लोहा चोरी हो गया या दूसरी और चीजों की भी चोरी हुई है जैसे कि एक नयी जीप भी चोरी हो गई है या किसी ने बेच दी है। अगर ऐसी कोई कम्प्लेंट आई थी तो क्या इसकी विजीलेंस इन्कवायरी हुई या नहीं, अगर हुई है तो उसका क्या नतीजा निकला है?

श्री जगदी । नेहरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा दहिया साहब को यह बताना चाहता हूँ कि कब मैटीरियल चोरी हुआ और कितने का हुआ, अब जीप चोरी हुई, इसके बारे में उनको पता होगा क्योंकि ये पहले वहाँ पर रजिस्ट्रार रहे हैं। मुझे इन सब बातों का पता नहीं है।

श्री भले राम: अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमिशन से भी ग्रांट मिलती है क्योंकि ये

कालेज के एग्जाम कंडक्ट करती हैं। हरियाणा में भी एक संस्था है जिसका नाम हरियाणा शिक्षा बोर्ड है। इसे आज तक सरकार ने कोई ग्रांट नहीं दी उसका भी बहुत बड़ा काम है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उसको भी कुछ ग्रांट देने के पर विचार करेगी।

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष: रोहतक यूनिवर्सिटी के बारे में ऐक्सपैंडीचर साइड पर सप्लीमेंटरीज मैम्बर साहिबान पूछना चाहते थे। मैंने उस क्वेश्चन को मंडे के लिए रैफर कर दिया है, इसलिए इस बारे में और सप्लीमेंटरीज मंडे को पूछ लीजिए।

Complaints received by Anti-Corruption committee

***87. Chaudhari Balbir Singh Grewal:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any Anti-Corruption Committee has been appointed by the Government; if so, the number of complaints of corruption against politicians, businessmen and the Government servants received by the said committee during the years 1977 to 1982 separately;

(b) the number of politicians, businessmen and Government servants out of those referred to in part (a) above, against whom inquiries were instituted during the same period separately; and

(c) the number of persons, if any, out of those referred to in part (b) above, as have been found guilty togetherwith the details of action, if any, taken against each one of them separately?

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल):

(क) इस समय कोई भ्रष्टाचार निरोधक समिति नहीं है। “ हरियाणा राज्य चौकसी समिति” नामक एक समिति ने प० श्री राम भार्मा की अध्यक्षता में तीन अन्य गैर-सरकारी सदस्यों सहित 3-8-77 से 26-11-77 तक कार्य किया। फिरप दोबारा प० श्री राम भार्मा पर आधारित एक सदस्य समिति ने 30-12-77 से 29-06-79 तक कार्य किया। इस समिति को गैर सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 868 रिक्वायर्मेंटें प्राप्त हुई थी। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध रिक्वायर्मेंटें इस समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं थी।

(ख तथा ग) यह सूचना एकत्रित करने में जो समय तथा परिश्रम लगेगा उससे विशेष लाभ नहीं होगा।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह सन्तोशजनक नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि नान आफिंशियल्ज के अगोस्ट 868 कम्प्लेट्स प्राप्त हुई। स्पीकर साहब, मुझे पेरी और सही इंफरमेंशन है कि उस सूची में जो कम्प्लेंट्स हैं उनमें इसके और इनके परिवार के नाम भी है। अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में एक

पोल्टरी फार्म हैं। उसका मालिक हर महीने तीन-चार साल तक यह चोरी करता रहा। इस तरह की कम्पलेट भी की हुई हैं। उस पोल्टरी फार्म में अंडों से चूजे बनते हैं। स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि हिसार में एक बहुत बड़ी फ़ैक्टरी है जिनका नाम जिन्दल फ़ैक्टरी है वहा पर भी बिजली की चोरी होती थी। चोरी पकड़ने से पहले वहां से गवर्नमेंट को दो लाख का रैवेन्यू आता था लेकिन पकड़ने के बाद वहां से सात लाख का रैवेन्यू गवर्नमेंट को आने लगा फिर उस एस0डी0ओ0 को वहां से बदल दिया गया। उस फ़ैक्टरी का मालिक बहुत बड़ा आदमी हैं। उसकी चौधरी भजन लाल से सांठ-गांठ है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बातें सच हैं या नहीं है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, दरअसल हमारे सामने दिक्कत यह है कि अपोजि उन के माननीय सदस्य जब खड़े होते हैं तो इनको सिवाए भ्रष्टाचार के और कोई बात नहीं दिखाई देती क्योंकि इनके जमाने में खूब भ्रष्टाचार था। जो आदमी जैसा होता है दूसरे को भी वह वैसा ही समझता है। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा है कि भजन लाल और परिवार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की रिक्वायत के बारे में किसी औथ कहता हूं कि अगर एक भी रिक्वायत आई हो और एक भी रिक्वायत के बारे में किसी ने पूछा हो तो मैं आज ही अस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जहां तक जिन्दल पाईप फ़ैक्टरी, हिसार का सम्बन्ध है, वे मुझे जानते हैं, मेरे साथ लगता हुआ उनका गांव, जिला भी एक ही है।

मै चौधरी देवी लाल की तरह नहीं हूँ जिन्होंने ओम प्रकाश के लिए कहा था कि वह मेरा बेटा नहीं है। स्पीकर साहब, जो मेरा दोस्त है उसके साथ मैंने हमें दोस्ती स्वीकार की है मैंने कभी मना नहीं किया। बहिन चन्द्रावती जी भी उनको जानती हैं और दूसरे मैम्बर साहिबान भी उनको जानते हैं। कौन सा मैम्बर ऐसा है जो उनको नहीं जानता?

अध्यक्ष महोदय, मैम्बर साहब ने कहा कि एस0डी0ओ0 ने चोरी पकड़ी और उसके खिलाफ कार्यवाही हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि यह बात आज ये मेरे नोटिस में लाए है। अगर कभी इन्होंने इस बारे में शिकायत की हो तो खड़े होकर कह दें। मैं गुनाहगार हूँ। इंक्वायरी करा देते हैं। अगर कोई कसूरवार पाया गया तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अगर इसमें सच्चाई नहीं हुई तो ये सोच लें कि अपने खिलाफ क्या कार्यवाही करवाएंगे।

स्पीकर साहब, पोल्टरी फार्मर्ज की मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है कि इस तरह की कोई शिकायत है या नहीं। कुल 868 कम्प्लेंट्स आई थी उनमें से 318 दरखास्तों की इंक्वायरी करके फाईल कर दिया गया और 108 दरखास्तों पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी। हमने उनको डिपार्टमेंट्स को कार्यवाही के लिए भेज दिया। अध्यक्ष महोदय, उन दरखास्तों में मोस्टली शिकायतें पंचों और सरपंचों के खिलाफ थी।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री महोदय के बारे में जो बात की गई, तो वह उनको बहुत नागवार गुजरी। इन्होंने कहा कि अपोजि इन वालों को तो हर जगह भ्रष्टाचार ही नजर आता है। अगर मुख्य मंत्री महोदय चाहते हैं कि क्लीन पब्लिक लाईफ रखी जाए तो क्या मुख्य मंत्री महोदय किसी हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं जो भ्रष्ट राजनीजिज्ञों और व्यापारियों की जांच कर सके?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, सारी बातों के लिए पहले से कानून बने हुए हैं। जो भी आदमी भ्रष्टाचार करता है, उसके लिए कानून है और उसको कानून के मुताबिक सजा मिलती है। हर आदमी के लिए कानून है चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो। स्पीकर साहब, डा० साहब के जमाने में चार मैम्बरज की एक कमेटी बनी थी, जिसमें चौधरी हरस्वरूप बूरा, राव रामनारायण और डा० बृज मोहन गुप्ता थे। उस पर काफी लोगों ने एतराज किया और कहा गया कि कमेटी पार्टीबाजी की बिना परिकायत मगवाती है। इसलिए वह कमेटी तोड़ दी गई। इसके पचात श्री राम कमेटी बनाई गई। अध्यक्ष महोदय मैं मानता हूँ कि पंडित श्री राम भार्मा बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ओनस्ट आदमी हैं, लेकिन उन पर भी लोगों ने अंगुली उठानी शुरू कर दी।

श्री मंगल सैन: मैं तो हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की बात कर रहा हूँ।

चौधरी भजन लाल: हाई कोर्ट के जज को भी बख़्शेगा नहीं। अध्यक्ष महोदय, असल में तो लोक आयुक्त होना चाहिए। हम इस बात पर विचार रहे हैं कि लोक आयुक्त बने या नहीं। इस पर हम पार्टी में सोचेंगे तथा अपनी हाई कमाण्ड से भी विचार विर्मल करेगें। अगर लोक आयुक्त बन जाए तो सियासी आदमियों को डर हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं।

श्री मंगल सिंह: आप आवासन कैसे दे दे लोक आयुक्त बना दिया जाएगा।

चौधरी भजन लाल: इस वक्त कैसे दे दें। हम तो अभी विचार कर रहे हैं।

श्री नेकी राम: स्पीकर साहब, हाउस आपके हाथों सेफ है और ये लोग यू ही दूसरे मैम्बरो पर ब्लेम लगाते हैं और हाउस का समय बरबाद करते हैं। तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस सारी कार्यवाही को हाउस की कार्यवाही में से निकाल दें। (हंसी)

Chaudhri Kulbir Singh Malik: I want to know from the Chief Minister....., Sir, whether any case was registered against the Chairman of the Marketing Committee, Kaithal regarding the embezzlement of Rs. 4 Lacs in earthwork?

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, अभी चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि अगरप इनके पास कोई स्पेसिफिक रिक्वायत आयेगी तो यह अवश्य एकान लैगे। मै आपकी मारफर इनसे यह जानना चाहता हू कि क्या इन्हे बिजली बोर्ड इम्पलाईज यूनियन की तरफ से कोई मैमोरेन्डम मिला है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक रिक्वायतों की तरफ सरकार को ध्यान दिलाया है और अगर मिला है तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि बिजली बोर्ड एक आटोनोमस बाडी है। अभी तक मेरे पास ऐसा कोई मैमोरेन्डम नहीं आया भी हो तो मैं इससे इन्कार नहीं करता, हो सकता है कि मैने न पढा हो क्योंकि उस समय मेरी आखों में खराबी थी। अगर आया होगा तो उस पर अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने डाक्टर मंगल सैन जी के प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि लोकायुक्त की अर्वायटमेंट के बारे में गौर करेगें। मुख्य मंत्री महोदय बतायेगें कि क्या इसी सैन में अपनी पार्टी की मीटिंग करके अगले हफते तक हाउस में इस बात का आवासन देगें और इस तरह का बिल लाने की कोशिश करेगें?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जल्दबाजी में ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती क्योंकि हमने अपनी पार्टी के साथ व हाई कमांड के साथ विचारविमर्श भी करना है। हमारी पार्टी कोई इनकी पार्टी की तरह थोड़ी है (व्यवधान एवं गोर) हम को निर्दिष्ट कर रहे हैं कि यहां पर भ्रष्टाचार का सफाया हो और जनता को स्वच्छ प्रशासन दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ कि हेली गांव के पुलिस अफसर रामफल के खिलाफ वहां के देहात वालों ने आन्दोलन कर रखा है और इस बारे में मुख्य मंत्री साहब को निर्दिष्टाकायत भी की गई है, लोग मिले भी हैं लेकिन अभी तक मुख्य मंत्री महोदय ने उस अफसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। यह बड़ा अहम मसला है। अध्यक्ष महोदय, आप मुख्य मंत्री जी से कहें कि इस बात की इन्कवायरी करवाई जाए।

(इस समय बहुत से माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए।)

Mr. Speaker: I have called for the next question. Please sit down. (Interruptions and noise) I have already allowed so many supplementaries on this question from the opposition side. Now I have called for the next question.

Financial position of Kurukshetra University

***94. Ch. Sahib Singh Saini:** Will the Minister of State for Education be pleased to state:-

(a) whether the Kurukshetra University experienced any difficulty in the disbursement of salaries to its employees during the months of September and October, 1982 on account of its difficult financial; and

(b) the present financial position of the University togetherwith the financial position of the University before the joining of the present Vice-Chancellor?

शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री (श्री जगरदीप नेहरा):

(क) मास सितम्बर, 82 में वेतन के भुगतान में कोई कठिनाई नहीं हुई, परन्तु मास सितम्बर का वेतन जो कि अक्टूबर में दिया जाना था के भुगतान में अस्थायी कठिनाई हुई थी। यह वेतन 4-10-82 को दिया गया था।

(ख) वर्तमान उपकुलपति ने 20-4-82 को कार्यभार संभाला था। वर्ष 1982-83 के विविद्यालय के बजट अनुमानों के पिछले वर्ष 1981-82 से चला आ रहा 22.94 लाख रुपये का घाटा दिखाया गया था। वर्ष 1982-83 में सरकार द्वारा इस विविद्यालय को 185 लाख रुपये की वार्षिक ग्रांट दी गई तथा इसके अतिरिक्त 75 लाख रुपये की विशेष ग्रांट विविद्यालय को दी गई है।

चौधरी साहब सिंह सैन: क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि 20-4-82 से पहले जो उप-कुलपति थे, उनका क्या नाम था ? साथ में जो कठिनाई वेतन देने में हुई, उसके क्या कारण थे ?

श्री जगदी । नेहरा: 20-4-82 से पहले श्री कुटप्पन उपकुलपति थे। वेतन देने में ऐसी कोई कठिनाई वाली बात नहीं थी, 1-10-82 को पे देनी थी लेकिन पे 4-10-82 को दी गई। वैसे ऐसी कोई कठिनाई वाली बात नहीं थी।

चौधरी साहब सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त श्री कुटप्पन उपकुलपति थे तो उन्होंने अपने आफिस के चारों तरफ बैरोकेड लगवा लिये थे और जो कुरुक्षेत्र कालेज था, उसके चारों और भी ऐसे ही बैरीकेड लगा दिये गये थे। यह जो वेसटफुल एक्सपैन्डीचर किया गया था, क्या इसी कारण से तो तनखाह देने में देरी नहीं हुई ?

श्री जगदी । नेहरा: स्पीकर साहब, मेरे माननीय सदस्य अगर इस बात का अलग से नोटिस देंगे तो मैं बता दूंगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, वाइस चान्सलर ने अपनी सेफटी के लिए बैरीकेड लगा भी लिये तो इसमें दिककत वाली क्या बात है क्योंकि नौजवान लड़के कभी कोई भारारत वगैरह भी तो कर सकते थे। मैं माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूँ कि जहां तक यूनिवर्सिटी को ग्रान्ट देने का ताल्लुक है, हमने 1981-82 में 235 लाख रूपये की ग्रान्ट दी और

1982-83 में 260 लाख रुपये की, मतलब यह है कि 25 लाख रुपये पहले से ज्यादा ग्रांट दी ताकि यूनिवर्सिटी की वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि वेतन देने में एक दो दिन की देर हो गयी आगे से किसी भी प्रकार की ऐसी परे तानी नहीं आने दी जाएगी।

श्रीमति चन्द्रावती: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जो वेतन वगैरह देने में डिले हुई है, क्या यह इन ऐफी गिऐन्सी की वजह से हुई है या पैस की कमी की वजह से हुई है ?

श्री जगदी ा नेहरा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को यह बतलाना चाहता हूं कि न यह डिले इन ऐफी गिऐन्सी की वजह से और न ही पैसे की वजह से हुई है।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि जो वेतन देने में देरी हुई है न तो वह इन ऐफी गिऐन्सी की वजह से और न ही पैसे की वजह से हुई है। क्या मंत्री महोदय बतालाएंगे कि फिर देरी से वेतन देने के क्या कारण थे, क्या कहीं यूनिवर्सिटी का दिवालिया तो नहीं निकल गया था जिसके कारण से ऐसा हुआ ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब को मैं बताना चाहूंगा कि जहां तनख्वाह 1-10-1982 को देनी थी या 2-10-82 को देनी थी वहां तनख्वाह 4-10-84 को दी गई, इसमें

कोई विशेष बात नहीं थी। कई बार बीच में छुट्टियां भी आ जाती हैं या कोई छुट्टी पर होता है तो इस कारण से ऐसा हो सकता है।

Sh. Mangal Sein: Sir, I am sorry to observe that the Hon'ble Minister is not prepared on the subject. He must come prepared and convince us.

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ।

चौधरी साहब सिंह सैनी: अध्यक्ष महोदय, अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने यह बतलाया कि वाइस चान्सलर ने इस वजह से कि कहीं नौजवान लड़के भारतरत्त न करें, अपनी सेफटी के लिए बैरिकेड लगवा लिये। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि विविद्यालय तो बीस बाईस सालों से चल रही है पहले तो कभी इस तरह की आवयकता नहीं पड़ी और आज इसकी आवयकता किन कारणों से पड़ी? इसके क्या कारण थे? यह जो वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर यिका गया है, क्या इस कारण से तो वेतन लेट नहीं दिया गया है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जिस समय किसी चीज की जरूरत होती है, वह उसी समय की जाती है। पहले जरूरत नहीं पड़ी इसलिए बैरिकेड नहीं लगाए गए और अब जरूरत पड़ी तो लगा दिये गये। अगर तनख्वाह दो दिन लेट हो जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। दो दिन में कोई

आसमान नहीं टूट जाता। दो दिन की बीच में छुट्टी भी आ सकती है और बैंक से पैसे लेने में भी कोई दिक्कत हो सकती है।

श्री मंगल सैन: अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि बैरिकेड लगाना तो एक मामूली सी बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर दुकान खोलकर बैठा है ?

श्री अध्यक्ष: देखिये, सब को पता है यूनिवर्सिटी की कन्टीन का जला दिया गया था। वहाँ पर आग लगी और गोलियाँ चलीं। इसलिए इन्तजाम तो करना ही पड़ता है।

Proclaimed offenders in the State

***73. Ch. Kulbir Singh Malik:** Will the Chief Minister be pleased to state the number of persons declared as proclaimed offenders by the courts in the State during the period from January, 1980 to-date togetherwith the number out of them who have been arrested?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): राज्य में 1-1-80 से 31-12-82 तक कुल 246 व्यक्तियों को उद्घोषित अपराधी घोषित कियसा गया था। इसी अवधि में 83 उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 68 अपराधियों के बारे में की गई घोशणा को कैन्सिल किया गया था।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, 246 में से 163 ओफ़ेंडर्स को हरियाणा पुलिस पकड़ नहीं सकी। मैं आपके

द्वारा मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह इन-एफि एंसी की बात नहीं है? दूसरे में यह जानना चाहता हूँ कि दो साल से ऊपर की सजा के कितने केस हैं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जा प्रोकलेमउ ओफेंडर्ज के केसिज हैं, उनमें ज्यादा रेलवे के केस होते हैं। रेलों में जो घटनाएं होती हैं उसमें ज्यादा बाहर के आदमी इनवाल्वड होते हैं। आप जानते हैं कि बाहर प्रान्तों के ओफेंडर्ज को पकड़ना इतना आसान नहीं होता लेकिन फिर भी हमारी पुलिस ने बहुत कोर्गि की। हमारी पुलिस की एफि एंसी सारे दे में अच्छी है और हमारी पुलिस का काम सब से अच्छा है। इस बात को अपोजि उन के भाई भी जानते हैं। इसके अलावा हमने हर जिले में इस बारे में स्टाफ मुकरर किया हुआ है जो हर तीसरपे महीने रेड करता है। हमारी कोर्गि है कि जो बाकी के ओफेंडर्ज पकड़ने रहते हैं, उनको भी पकड़ा जाए।

श्री राम बिलास भार्मा: अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि 68 ओफेंडर्ज के बारे में प्रोक्लेमें उन कैसिल करनी पड़ी। मैं जानना चाहता हूँ कि यह कैसिल क्यों करनी पड़ी?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसा होता है कि ओफेंडर या तो स्रेंडर कर देता है या कोई मर जाता है इसलिये कैसिल करनी पड़ती है। (गोर)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि 68 में से ऐसे कितने लोग हैं जो मर गये? और इन 68 औफैंडर्ज के बारे में स्पॅसिफिक डिटेल्ज जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: राम बिलास जी, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि आप जिस वक्त चाहें उठकर जो मरजी में आये कह दे। सप्लीमेंटरी परमिशन के साथ की जा सकती हैं।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि दो साल से ऊपर की सजा के कितने केस हैं।

चौधरी भजन लाल: आपने 1-1-80 से 31-12-82 तक की सूचना पूछी थी और वह हमने जवाब में बता दी है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: मैं अब सप्लीमेंटरी के द्वारा पूछता हूँ कि दो साल से ऊपर की सजा के कितने केस हैं?

चौधरी भजन लाल: यह तो आप ने सवाल में पूछा नहीं था। यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। इसके लिए अलग से नोटिस चाहिये।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि 246 आदमियों को 1-1-80 से 31-12-82 तक प्रोक्लेम्ड औफैंडर घोषित किया गया। क्या वे रिकार्ड देख कर

बताएंगे कि वे किस- किस जुर्म में पकड़े गये? क्या इनमें कोई ऐसा भी था जो जेल से भागा हुआ हों?

चौधरी भजन लाल: ये आकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, इसमें चोरी, डकैती और कत्ल के केस भी हो सकते हैं। बहुत से बाहर के लोग भी होते हैं जो चोरी करके भाग जाते हैं।

Tourist Complex at Ambala Cantt.

***102. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister of State for Technical Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up a Tourist Complex at Ambala Cantt; and

(b) if so, the details thereof and the time by which the aforesaid complex is likely to be set-up?

Minister of State for Technical Education (Shri Lachhman Dass Arora):

(a) Yes

(b) Initially a restaurant, some accommodation for tourists and landscaped gardens etc. are proposed to be provided in this complex. Depending on the availability of funds, the setting up of this complex will take about two years.

सेठ राम दास धमीजा: अध्यक्ष महोदय, अम्बाला कैंन्ट के बारे में मैं यह कहूंगा कि यह हरियाणा में सब से खूबसूरत और

बढिया भाहर है औरप यह दूनिया के नक्शे पर हैं। मै यह जानना चाहता हूं कि वहां पर यह सुन्दर टूरिस्ट कम्पलैक्स कहा पर बनाया जाएगा? क्या यह कम्पलैक्स दो साल की बजाए पहले बना दिया जाएगा?

श्री लछमन दास अरोड़ा: स्पीकर साहब, धूलकोट में जो रेलवे का पुल है वह अम्बाला सिटी ओर बलदेव नगर कैम्प के बीच में पड़ता है। टूरिस्ट कम्पलैक्स के लिये वहां पर जगह ली गई है।

चौधरी हुकम सिंह फागट: मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नरवाना के टूरिस्ट कम्पलैक्स का काम कब तक भुरू कर दिया जाएगा?

श्री लछमन दास अरोड़ा: वहां पर जगह एक्वायर हो चुकी है। उम्मीद है अगले साल काम भुरू हो जाएगा।

चौधरी भागमल: मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अम्बाला वाले टूरिस्ट कम्पलैक्स की जगह क्या तलाश कर ली गई है और क्या वहां पर जमीन एक्वायर कर ली गई है?

श्री लछमन दास अरोड़ा: जी हां, वहां पर जगह एक्वायर कर ली गई है।

श्री निहाल सिंह: धमीजा साहब ने कहा कि टूरिस्ट कम्पलैक्स के लिए खूबसूरत जगह होनी चाहिए। मै जानना

चाहता हूँ कि जगह सिलैक्ट करने के लिये क्य क्राइटेरिया बनाया जाता हैं? क्या नारनौल जैसी बदसूरत जगह के लिये भी कम्पलैक्स बनाने का कोई विचार है?

श्री लछमन दास अरोड़ा: स्पीकर साहब, नारनौल में आलरेडी टूरिस्ट कम्पलैक्स बना हुआ हैं।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय मैं आपकी इजाजत से इस सवाल से मिलती-जुलती सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिले में ओटू पुल के पास एक झील है और वहा पर एक टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाने की सरकार की एक स्कीम थी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उस झील पर टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाया जाएगा?

श्री लछमन दास अरोड़ा: स्पीकर साहब, वहां पर टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाने की कोई बात सरकार के जेरेगौर नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वैसे वहां पर पंचायत ने एक टूरिस्ट कम्पलैक्स बना लिया हैं।(गोर)

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया है कि वहां पर एक टूरिस्ट कम्पलैक्स पंचायत ने बना लिया हैं। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूँ कि वह टूरिस्ट कम्पलैक्स औटू गांव के एक ठाकूर ने गांव से बाहर अपने खेत में अपनी कोठी के पास बनाया हुआ हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हैं कि क्या

किसी इनडिविजुअल को फायदा पहुंचाने के लिए उसके खेत में टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाया जा सकता है?

श्री लछमन दास अरोड़ा: जो कम्पलैक्स वहां बनाया गया है, वह पंचायत विभाग ने बनाया है, इसलिए उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इस बारे में पंचायत विभाग ही जवाब दे सकता है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, टूरिस्ट कम्पलैक्स ऐसे स्थानों पर बनाए जाने चाहिए जहां पर सरकार को आर्थिक लाभ हो और लोगों को फायदा हो। कई ऐसे कम्पलैक्स हैं, जिनमें घाटा हो रहा है। स्पीकर साहब, गोहाना तहसील ऐसी जगह पर स्थित है जिसके आस-पास जींद, सोनीपत, रोहतक और पानीपत का ऐरिया लगता है और वहां पर कोई टूरिस्ट कम्पलैक्स नहीं बनाया हुआ। एक बार मुख्य मंत्री जी वहां गए थे तो उन्होंने यह वायदा किया था कि गोहाना में एक टूरिस्ट कम्पलैक्स बना देंगे। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या गोहाना में टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाने के बारे में सरकार की कोई प्रपोजल है?

श्री लछमन दास अरोड़ा: ऐसी कोई प्रपोजल सरकार के जेरे गौर नहीं है। यदि माननीय सदस्य इस बारे में लिख करके भेजेंगे तो उस पर गौर किया जा सकता है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या जमीन बिना एक्वायर किए किसी व्यक्ति की जमीन पर टूरिस्ट कम्प्लैक्स खोला जा सकता है?

श्री लछमन दास अरोड़ा: स्पीकर साहब, किसी भी प्राईवेट आदमी की कोठी किराए पर लेकर कम्प्लैक्स खोला जा सकता है। अगरप परमानेंट कम्प्लैक्स बनाना हो तो जमीन एक्वायर करनी पड़ती है।

ठाकुर बहादुर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सिरसा जिले में कितने टूरिस्ट कम्प्लैक्स बनाए जा चुके हैं, कितने और कम्प्लैक्स बनाने की प्रपोजल सरकार के विचारधीन है और जितने कम्प्लैक्स बनाए हुए हैं उनकी क्या हालत है, वे घाटे में जा रहे हैं या फायदे में हैं? अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे भाई भागी राम जी ओटू झील पर जो कम्प्लैक्स बना हुआ है उसके बारे में एतराज कर रहे थे मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि सिरसा में जिला हैडक्वाटर पर एक टूरिस्ट कम्प्लैक्स बनाया हुआ है उसमें रिहायास का कोई प्रबंध नहीं है। इसी तरह से एक काला तीतर नाम का कम्प्लैक्स बनाया हुआ है वह मेरे भाई श्री भागी राम जी के नेता के राज में बनाया गया था वह कम्प्लैक्स घाटे में चल रहा है उसका कोई फायदा नहीं है और न ही वह पब्लिक के यूज में आता है। (गौर एव विघ्न) मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने काला तीतर कम्प्लैक्स के लिए कोई कमेटी बनाई है जो देखें कि

वह कम्पलैक्स ठीक तरह से चल सकता है या नहीं क्योंकि उसमें बहुत घाटा है? (गोर एव विधन)

श्री अध्यक्ष: वीरेन्द्र सिंह जी आप कम से कम अपनी पार्टी के मैम्बरज को समझाएं। यह मुझे देखना है कि माननीय सदस्य सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं। अगर वे अपनी सप्लीमेंटरी को ज्यादा लम्बी ले जायें तो मैं खुद उनको टोक सकता हूँ। लेकिन आप सभी खड़े होकर यह कहें कि ये सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं, यह कोई बात नहीं है। आप सभी ने खड़े होकर हल्ला-गुल्ला भुरू कर दिया है। ऐसा करना एम0एल0ए0 के लिए कोई भान की बात नहीं है। मैं अभी यह सोच ही रहा गि कि मैं उनको यह कहूँ कि आप सप्लीमेंटरी को इतना लम्बा न करें, आप अपनी सप्लीमेंटरी को छोआ करे लेकिन बात सभी एकदम खड़े हो गए और भाोर करना भुरू कर दिया। मैं यह पसंद नहीं करता।

ठाकूर बहादूर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि काला तीतर में जो कम्पलैक्स बनाया हुआ है वह बहुत घाटे में चल रहा है उसका कोई फायदा नहीं है क्या उसकी जांच करने के लिए सरकार ने कोई कमेटी मुकरर की है?

श्री लछमन दास अरोड़ा: स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि काला तीतर टूरिस्ट कम्पलैक्स बहुत घाटे में चल रहा है।

उसके कलए हमने दो-तीन आफिसर्ज की डियूटी लगी दी हैं। वे आफिसर्ज उसके मुताबिक फैसला करने अपनी राय सरकार को देंगे। उसके बाद उसका फैसला किया जाएगा।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं यह सप्लीमेंटरी मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी एम0एल0ए0 के किसी रि तेदार को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए उसके खेत में टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाया जा सकता है? ओटू झील पर जो कम्पलैक्स बनाया गया है यह पब्लिक की मनी मिसचूज किया गया है। (गोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, बहन जी बहुत सीनियर मैम्बर हैं। इनको यह पता होना चाहिए कि जब परमानेंट कम्पलैक्स बनाया जाता है जो उसके लिए जमीन एक्वायर करनी पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि किसी आदमी का मकान किराए पर लेकर कम्पलैक्स खोला जाए तो उसके लिए जमीन एक्वायर करने की कोई आव यता नहीं है। ओटू झील पर जो कम्पलैक्स है, उसकी बिल्डिंग वहां की पंचायत ने किराए पर ले कर कम्पलैक्स खोला है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि काला तीतर टूरिस्ट कम्पलैक्स चौधरी देवी लाल जी ने बनाया था। अध्यक्ष महोदय, वहां पर टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाने का कोई मतलब नहीं था। वह कम्पलैक्स मेन रोड़ से डेढ दो मील दूर है। पता नहीं वहां पर कम्पलैक्स बनाने की चौधरी देवी लाल जी की क्या मं ा थी। उस कम्पलैक्स में एक महीने

अन्दर एक भी आदमी के ठहरने की औसत नहीं हैं। पता नहीं चौधरी देवी लाल जी ने वहां पर इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया। आज की सरकार ऐसे काम नहीं करती।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, क्या बाती सभी कम्पलैक्स फायदे में चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर, अब क्वै चन आवर खत्म होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों
के लिखित उत्तर

Cultivable Land

***76. Shiri Lachhman Singh Kamboj:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that cultivable land of certain villages in the State has been rendered useless by river Yamuna or has come under it:

(b) if so, the total number of such village togetherwith the details of the steps, if any, taken to rehabilitate the affected persons; and

(c) the number of persons out of those referred to in part (b) above, who have actually been rehabilitated so far togetherwith the amount of compensation, if any, given to such persons as have suffered losses?

राजस्व मंत्री(चौधरी फूल चन्द):

(ए) जी नहीं।

(बी तथा सी): प्र न पैदा नहीं होता।

Bridge on Drain No.8 at village Titoli

***266. Sh. Hari Chand Hooda:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether sanction for the construction of a bridge on drain no.8 at village Titoli of district Rohtak has been accorded; is so, the date by which the construction thereof is likely to be started?

लोक निर्माण राज्य मंत्री(चौधरी गोवर्धन दास चोहान):
जी हां। निर्माण कार्य वित्त वर्ष 1983-84 में भूरू किये जाने की सम्भावना है।

**Discharge of polluted water of Yamuna Nagar
Factories in tho the Western Jamuna Canal**

***241. Master Ram Singh:** Will the Minister of State for Public Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the polluted water released by various industries in Yamuna Nagar is discharged into the Western Yamuna Canal;

(b) if so, whether the said polluted water has resulted in insanitary conditions endangering the health of the inhabitants and health and lives of cattles of the villages

located on both sides of the Western Jamuna Canal such as Jabbal, Kanjnu, Radaur, Dhaulra, Khurdban; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative the steps, if any taken or proposed to be taken to check the discharge of the said polluted water into the Western jamuna Canal?

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह):

(ए) जी हां

(बी) किसी मानव व पशु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, यदपि प्रदूषण अवांछित है।

(सी) हरियाणा राज्य प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड चण्डीगढ़ ने यमुनानगर के बड़े-बड़े उन उद्योगों के विरुद्ध जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत सक्षम न्यायालयों में मुकदमे दायर किये हैं जो कि पिछमी यमुना नहर में बहिःस्त्राव का निस्सउण कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप कुछ उद्योगों ने अपने बहिःस्त्राव को ट्रीट करने के लिए निवारण संयंत्र का निर्माण शुरू कर दिया है।

**Foundation stones for the construction of Civil Hospitals
in the State**

***274. Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the names of the place, if any, in the State where foundation stones for the constructing of Civil Hospital were laid during the period from 1-1-80 to date; together with the date/dates on which the foundation stones were laid;

(b) whether any funds have been allocated for the construction of any of the Hospitals, referred to in part(a) above; if so, details thereof; and

(c) the names of the Hospital, if any, out of those referred to in part(a) above, the construction of which has been completed or is likely to be completed before 31-3-1983, separately?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) दिनांक 1-1-1980 से आज तक सामान्य अस्पताल, अम्बाला, खरहर सोनीपत, बी०के० अस्पताल, फरीदाबाद और ग्रामीण हस्पताल, गुलहा के िालान्यस क्रमं ा दिनांक 11-2-1980, 1-3-1980, 31-03-1980, 31-8-1981 और 16-5-1980 को किये गये ।

(ख) उपरोक्त अस्पतालों के नये भवन निर्माण पर दिनांक 31-3-1982 तक अम्बाला मे 5.50 लाख, खरहर में 11.55 लाख और सोनीपत में 10.98 लाख रूपये खर्च किये गये । वर्ष 1982-83 में अम्बाला के लिए 12.00 लाख रूपये, खरहर के लिए 2.00 लाख और सोनीपत के लिए 16.00 लाख रूपये की राशि एलोकेट की गई थी ।

(ग) दिनांक 31-03-1983 से पूर्व सामान्य अस्पताल, खरहर के भवन के पूर्ण हो जाने की संभावना है।

Declaration of Tahsil Kaithal as District

***275. Shiri Nar Singh:** Will the Minister for Health be pleased to State—

(a) the number of persons/Firms granted licenses for the manufacture of medicines in the State during the period from 1-11-66 to date;

(b) whether any cases of manufacture of Sub-Standard or spurious medicines by the person/firms, referred to in part (a) above, have come into the notice of the Government; if so, the number thereof and the action, if any, taken against the guilty person/firms;

(c) whether the licenses of any of the person/firms, referred to in part (b) above were cancelled; and

(d) if so, whether any of the person/firms, referred to in part (c) above, were granted licenses again on their changing the names of their firms?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) 481

(ख) हां, 1419

2. संबंधित लाईसैंसिज के विरुद्ध निम्नवर्णित कार्यवाही की गई है:—

1. मुकदमे दायर किए गए—3
2. संबंधित प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए लाईसेंसिज रद्द किए गए—77
3. लाईसेंसिज निलम्बित किए गए—4
4. चेतावनी दी गई—196
5. पार्टिज जिन को माल बेचा गया था से जो माल न बिका था वापिस निर्देा दिए गए।—1139

(ग) हां,6

(घ) नहीं।

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Payment of salaries to the privately managed Colleague Teachers.

***26. Prof. Sampat Singh:** Will the Minister of State for Education be pleased to State—

(a) the number of privately managed colleges in the State where teachers have not been paid their salaries for more than tow months; and

(b) the steps, if any, taken to ensure regular payment of salaries to the teachers referred to in part (a) above?

***Interim Reply**

The un-Starred Assembly Question No. 26 appearing in the list of Unstarred Questions on 10-03-1983 in the name of Prof. Sampat Singh, M.L.A. is not ready.

The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-

State Minister Education

The Secretary,

Haryana Vidhan Sabha

Chandigarh.

U.O. No.39/6/83 Edu-1(2) Dated Chandigarh 9.3.83

Parity in pay scales of College D.P.Es and Teachers.

27. Prof. Sampat Singh: Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether Librarians and D.P. Es. working in the colleges have been given parity in the matter of pay scales with college teachers by the U.G.C., and

(b) if so, the time by which the recommendation of the U.G.C., is likely to be implemented?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा):

(क) हां—यू. जी. सी. ने लाईब्रेरियन/डी.पी.ई.जी. को प्रध्यापक ग्रेड 01.04.80 से निर्धारित योग्यता रखने वालों को देने के लिए सहमति दे दी है।

(ख) यू. जी. सी. द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की योग्यता बारे छान-बीन की जा रही है। संशोधित वेतनमान छान-बीन उपरांत भीष्म लागू कर दिए जाएंगे।

Grants released to M.D. University, Rohtak

28. Prof. Sampat Singh: Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) the amount of grants released to M.D. University, Rohtak during the last five years;

(b) the amount out of the amount referred to in part (a) above granted for the construction of Buildings etc.; and

(c) whether the amount of the said grants has been utilised for the proposes for which it was allocated?

Interim Reply

The Un-starred Assembly Question No. 28 appearing in the list of Unstarred questions on the 10th March, 1983 in the name of Prof. Sampat Singh, M.L.A. is not ready.

The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

SD/-

State Minister Education

The Secretary,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh

U.O. No.47/18/83 EDU-I(6) dated the 7th March,
1983.

Closing of Irrigation department Circles

29. Prof. Sampat Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number for circle of the irrigation Department, if any, which were closed during the last two years and the number of circles likely to be closed together with the reasons thereof;

(b) the number of employees retrenched as a result of closing of the circles referred to in part(a) above; and

(c) whether there is any proposal to absorb the retrenched employees referred to in part (b) above?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह):

(क) पिछले दो वर्षों के कोई भी सर्कल बनद नहीं किया गया। कुछ सर्कल समाप्त करने का मामला सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Tax Exemption to the Films

36. Smt. Basanti Devi: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the number of films granted exemption from the payment of tax/taxes in the State since the formation of the present Government in 1982 to date;

(b) the total amount of loss of revenue to the State Exchequer suffered on account of the exemption as referred to in part(a) above during the same period ;and

(c) whether any firm policy has been formulated by the Government to grant tax exemptions to the films; if so, details thereof?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री बृज मोहन):

(क) 11.

(ख) चूंकि जिन फिल्मों को छूट प्रदान की गई हैं उनमें से कुछ अभी तक प्रदर्शित नहीं की गई हैं, अतः इस स्टेज पर वास्तविक हानि के आकड़े बताना संभव नहीं है।

(ग) छूट उन मनोरंजनों, फिल्मों सहित, प्रदान की जाती हैं जो भ्रान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सदभाव को बढ़ावा देते हों या कला तथा खेल-कूद या किसी और जनहित को प्रोत्साहन देते हों। जहां तक फिल्मों को सम्बन्ध है इनके अक्सर 10 प्रिन्ट्स को एक सप्ताह के लिए छूट प्रदान की जाती है।

New pay scale for the employees of Boards and corporations.

37. Chaudhri Kulbir Singh Malik: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether the benefit of revised pay scales, applicable w.e.f. 1.04.1979, has been allowed to the employees of all the Boards and Corporations in the State which are owned or controlled by the Government; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative the names of such corporations/Boards whose employees have not been given the revised pay scales together with the reasons therefore and the time within which employees of such Boards/Corporations are likely to be allowed the benefit of revised scales of pay?

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर):

(क) हां, राज्य के अधीनस्थ सभी मण्डलो / निगमों के कर्मचारियों को सं गोधित वेतनमानों का लाभ दे दिया गया है। इस लाभ दे दिया गया है। इस लाभ से अभी तक वे लाभाविन्त नही हुए हैं जो कि अनुबन्ध-II में द ार्ये हैं। अनुबन्ध-I में ऐसी निगमों / मण्डलों जहां कि सं गोधित वेतनमानों का लाभ और जिस तिथि से यह लाभ दिया गया है, को द ार्या गया है।

(ख) हरियाणा बुरीज को भारी मात्रा में इक्टी हुई वित्तीय हानि के दृष्टिगत उन्होने अपने कर्मचारियों को सं गोधित वेतनमानों का लाभी अभी तक नही दिया है। हरियाणा कृशि उधोग निगम तथा हरियाणा राज्य लघु उधोग एव निर्यात निगम लिमिटेड के कुछ तकनिकी कर्मचारी जिनका वेतन सं गोधन अभी तक नही किया गया है, वे या तो संकुचित वेतनमान ले रहे थे अथवा उनके सामान्तर पद हरियाणा सरकार मे नही थे। हरियाणा बुरीज के कर्मचारियों तथा हरियाणा सरकार में नही थे। हरियाणा बुरीज के कर्मचारियों तथा हरियाणा कृशि उधोग निगर / हरियाणा राज्य लघु उधोग एवं निर्यात निगम के बची हुई श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों का सं गोधन विचाराधरन है और ि ाघ ही किए जाने की सम्भावना है।

Annexure-I

Name of the Corporations	Date of
--------------------------	---------

		revision of the pay scale
	1	2
1	The Haryana State Cooperative Supply	1-4-79
2	Haryana Warehousing Corporation	1-4-81
3	Haryana Harijan Kalyan Nigam Ltd.	1-4-79
4	Haryana State Handloom & Handicrafts Corporation Ltd.	1-4-79
5	Haryana State Minor Irrigation(Tube wells) Corporation Ltd.	1-4-79
6	Haryana Land Reclamation & Development	1-4-79
7	Haryana Tourism corporation Ltd.	1-4-82
8	Haryana Backward Classes Kalyan Nigam Ltd.	Date of the constitution of the corporation during 1980-81.
9	Haryana Seeds Development Corporation Ltd.	1-4-79

10	Dairy Development Corporation	1-4-79
11	Haryana State Cooperative Development Federation Ltd.	1-4-79
12	Haryana Financial Corporation	1-4-79
13	Haryana Agro-Industries Corporation	1-4-79
14	Haryana State Small Industries & Export Corporation Ltd.	1-4-79
15	Haryana State Industrial Development corporation	1-4-79
Boards		
1	Haryana State Electricity Board	1-4-79
2	Haryana State Board for the Prevention & Control of Water Pollution.	1-4-79
3	Housing Board	1-4-79
4	Haryana State Social Welfare Advisory Board	1-4-79
5	Agriculture Marketing Board	1-4-79
6	Haryana State Khadi Gram Udhog Board	1-4-79
7	Haryana Urban Development Authority	1-4-79

8	Haryana Education Board, Bhiwani	1-4-79
Banks		
1	Haryana State Cooperative Bank	1-4-79
2	Haryana State Cooperative Land Development Banks	1-4-79

Annexure-II

1. Haryana Breweries Ltd.

2. The following posts in the Haryana Agro Industries Corporation Ltd.

(i) Technical Posts in the Aviation Wing.

- (a) Junior Mechanic
- (b) Senior Mechanic
- (c) Field Officer
- (d) Agricultural Aircraft Engineer
- (e) chief Aircraft Engineer
- (f) Spray Pilot/Sr. Spray Pilot

(ii) Other Technical posts.

- (a) Production Manager, Cattle Feed Plant Jind;
- (b) Asstt. Chemist

(c) Lab. Chemist

(d) Jr. Food Technologist

3. Some technical posts of Haryana State Small industries & Export Corporation Ltd.

प्वायंट आफ आर्डर

क्षेत्रीय तथा जल विवाद सम्बन्धी रैजोल्यू इन को अस्वीकार करने सम्बन्धी

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मैने दो लाइन का एक रैजोल्यू इन दिया था जो इस प्रकार था—

“This House recommends that the 1970 award regarding territorial dispute between Punjab and Haryana and 1981 agreement regarding the water dispute may be fully implemented forthwith.

आपके आफिस की तरफ से उसका जवाब यह आया है कि रूल 174 के तहत यह रैजोल्यू इन एडमिट नही किया जा सकता, इसलिए यह डिस-अलाऊ किया जाता है। स्पीकर साहब, मैने रूल 174 सारा पढ लिया है। इसमें कही भी ऐसा नही है जिसके तहत यह रैजोल्यू इन डिस-अलाऊ किया जाए और जो मैने रैजोल्यू इन दिया है, उसमें भी ऐसी कोई खामी नही है जिसके बिना पर वह डिस-अलाऊ किया जाए।

Mr. Speaker: Rule 174 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly reads as under:-

“In order that a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:-

(a) it shall be clearly and precisely expressed, and shall raise substantially one definite issue;

(b) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions or defamatory statements, nor shall it refer to the conduct or character of persons except in their official or public capacity;

(c) it shall not relate to any matter which is not primarily the concern of the State Government;

(d) it shall not relate to any matter which is under adjudication by a Court of Law having Jurisdiction in any part of India”

The resolution has, therefore, been disallowed because it did not meet the requirement of the Rule and it did not raise substantially one definite issue.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, 1970 का जो अवार्ड है और 1981 का जो एग्रीमेंट है उसको लागू करवाने के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होनी चाहिए। इस मामले पर सभी एजिटेटिड हैं and it is an important issue. इसमें सारे हरियाणा को इन्ट्रेस्ट है।

श्री अध्यक्ष: गवर्नर एड्रेस पर भी इस मैटर को रेज कर सकते हैं तथा बजट आदि पर भी इस बारे में मैम्बर साहेबान अपने विचार रख सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यदि रैज्योल्यू इन पर बहस हो जाती है तो इस पर सारे हाउस की मोहर लग जाएगी। इसमें विपक्ष को भी इन्ट्रेस्ट है जितना ट्रेजरी बैचिज का। इस पर हाउस के किसी भी मैम्बर को कोई एतराज नहीं है। इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि इसी सम्बन्ध में अपोजि इन के दो सदस्यों की ओर से रूल 84 के तहत मो इन आया है जो एडमिट कर लिया गया है, उस में से सारी बातें आ जाएंगी। उस पर डिस्क इन होगी, उस समय आप बोल देना।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरी तो यही गुजारि है कि आप इसको एडमिट कर ले। आप बे एक मुख्य मंत्री जी से पूछ लें। इस पर उनको भी कोई एतराज नहीं होगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं बोलने के लिए आप से इजाजत चाहता हूँ यह कहने के लिए मुझे माफ करे कि यह बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। इसको यहाँ पर आप डिस्कस नहीं करने दे रहे हैं। इसमें हरियाणा की जनता का हित जुड़ा हुआ है। सारे हरियाणा के एम0एल0ए0 इसमें इन्ट्रैस्टिड हैं। कल भी मुख्य

मंत्री जी एक प्रस्ताव बगैर हमारे से पूछे ले आये थे। उसमें भी सारे हरियाणा का हित जुड़ा हुआ था। यदि ये उस प्रस्ताव के बारे में पहले ही पूछ लेतम तो हम भी उसमें अपना योगदान देते। यदि ये उस प्रस्ताव के साथ हरियाणा की एक करोड़ 10 लाख जनता का हित जुड़ा हुआ था। यदि वह प्रस्ताव सबकी राय से हाउस में लाया जाता तो उसका इमप्रैान और भी अच्छा होता। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इसे एडमिट कर लें।

श्री अध्यक्ष: आप मुझे एक बात बताएं कि क्या मेरा हरियाणा के हित में इन्ट्रैस्ट नहीं है? क्या मैं हरियाणा का रहने वाला नहीं हूँ?

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा।

श्री अध्यक्ष: दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब मैंने रूलिंग दे दी है तो उसके बाद भी आप बोल रहे हैं। This is not fair.

श्री मंगल सैन: इस बारे में मेरी आपसे रिकवैस्ट है कि आप इस रैजोल्यूशन को एडमिट कर लें। We have the right to request you to review your decision.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, आपकी रूलिंग को कोई चैलेंज नहीं कर रहा।

Mr. Speaker: I have already given my ruling. the Hon'ble Member can raise this matter on other different occasion. there will be no more discussion on this now.

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूल अध्यापकों की मांगो सम्बन्धी

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मेरी एक काल अटैन्डान्स मोडल टीचरों के सम्बन्ध मे थी।.. . . .

श्री अध्यक्ष: वह डिस-अलाऊ कर दी है और उसका जवाब आपको भेज दिया है।

प्रोफेसर सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, * * * * *

श्री अध्यक्ष: मेरी इजाजत के बगैरप जो बोला जा रहा है, वह रिकार्ड न किया जाएं।

प्रोफेसर सम्पत सिंह: * * * * *

श्री अध्यक्ष: मैं इस तरह बोलने के लिए सब को तो नहीं कह सकता। लेकिन लीडरज आफ दि पार्टी को जरूर रिक्वैस्ट कर सकता हूँ कि वे अपने मैम्बरों को समझाएं कि हाउस में इन्हे इस तरह नहीं बोलना चाहिए। एक मैम्बर बोल रहा है और वह अभी अपनी बात को अपनी तरफ से पूरी भी नहीं कर पाया है कि ये बीच में बोलने लग गए। और वह भी वह मैम्बर जा अपने

आपको प्रोफेसर कहलाता हों। कुलबीर सिंह जी अपनी बात कह भी नहीं पायें कि व बग़र परमि इन के बोलने लग गए।

Shri Verender Singh: We are sorry for that स्पीकर साहब, उन्होंने तो इस इम्प्रै इन में बोलना भुरु कर दिया कि कुलबीर सिंह जी की बात खत्म हो गई हैं।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, सी0एम0 साहब दो—तीन बार कह चुके हैं कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को बराबर के ग्रेड दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: उसका जवाब मैंने आपको भेज दिया है। उस काल अटैन् इन मो इन को मैंने डिस—अलाऊ की दिया है।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: मेरे पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: अगर अभी नहीं पहुंचा तो पहुंच जायेगा।

मास्टर िव प्रसाद: स्पीकर साहब, मान्यता प्राप्त स्कूलों में काम कर रहे टीचरों को सरकारी स्कूलों में काम कर रहे अध्यापकों में बराबर ग्रेड देने के बारे में सी0एम0 साहब ने कई बार आ वासन दिलाया है। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कुछ कार्यवाही नहीं की गई इस संबंध में जा काल अटैन् इन मो इन दिया गया है, उसको उनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मास्टर जी, आप बैठिये। यदि कोई धरने पर बैठ जाये या किसी को कोई पेमेंट न मिले तो इसका यह मतलब नहीं कि उन सबके बारे में काल अटैन्शन नोटिस एडमिट कर लिए जाए। इस संबंध में जो काल अटैन्शन नोटिस आये हैं, वह मैंने डिस अलाऊ कर दिये हैं। चैन फसस्ट्स, स्ट्राइक्स तथा धरना आदि इन मोशन का सब्जेक्ट नहीं बनती।

(ii) कौसली में किसानों के सम्मेलन में नुकसान पहुंचाने सम्बन्धी

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, रोहतक के पास कोसला नाम के एक कस्बे के अन्दर किसानों का एक सम्मेलन 27.02.1983 को हो रहा था। उसके अन्दर सारी अपोजिशन के लोग गए हुए थे। वहां पर एम0पी0 इन्द्रवेंकटराव भी आये हुए थे और जनता पार्टी के सदस्य यादव जी भी आये हुए थे। वहां पर जो लोग ट्रैक्टर या ट्रक लाये हुए थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। वहां पर एक ऊंट की टांग टूट गई थी। हमने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। इस संबंध में जो मेरी काल अटैन्शन थी, उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: यह आपकी काल अटैन्शन मेरे पास अभी तक नहीं पहुंची है मैं इसका जरूर कन्सीडर करूंगा।

श्री मंगल सैन: धन्यावाद सर।

(iii) अम्बाला भाहर में गुरुद्वारा मंत्री साहब को घेरा डालने तथा वहां पर तनाव होने सम्बन्धी

Chaudhri Sahab Singh Saini: I have given a notice of adournment motion regarding surrounding of Gurdwara Manji Sahib in Ambala City and the tenstion thereby caused among the people.

श्री अध्यक्ष: यह मामला सब-जुडिस हैं। हाईकोर्ट में केस चल रहा हैं। इसलिए मैने इनको डिस अलाऊ कर दिया हैं।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, आज अखबार में आया हैं कि इस संबंध में जो अपील हाई कोर्ट में की गई थी वह रिजैक्ट हो चुकी है। इस गुरुद्वारे को जो कमेटी चलाती हैं उसके लिए एक रिसिवर नियुक्त किया गया था। पुलिस उसको भी अन्दर नहीं जाने दे रही हैं।

Mr. Speaker: I am very Sorry. I have disallowed it.

चौधरी साहब सिंह सैनी: झगड़ा यह है कि पुलिस उसको घेरे खड़ी है। झगड़ा यह नहीं हैं कि कोर्ट में केस चल रहा हैं। वहां पर पुलिस सिविल ड्रैस में भी घूम रही हैं और लोगों को तंग कर रही है।

Mr. Speaker: I have disallowed you motion on the following grounds that:-

1. the motion is not supported by explanatory memorandum as required under rule 67(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly;

2. the aggrieved party, if any, may seek remedy through the court of law; and

3. the subject-matter of the motion is related with day-to-day administrative nature.

चौधरी साहब सिंह सैनी: मैंने जो मोशन दिया है उसके अन्दर सारी बातें लिखी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। जितनी हमदर्दी गुरद्वारा के प्रति आपकी है, उतनी ही हमदर्दी मेरी भी है और मैं धार्मिक स्थलों की पूरी इज्जत करता हूँ। लेकिन यदि वहाँ पर ला एण्ड आर्डरप कि स्थिति खराब हो जाये और वहाँ पर लोग बरछे तथा भाले आदि लेकर मार काट पर उतर आये तो क्या पुलिस कुछ भी कार्यवाही नहीं करेगी? वहाँ पर दोनों पार्टियों में झगड़ा हो गया था जिस कारण पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मैंने आपके उस नोटिस को डिस-अलाऊ कर दिया है and i have announced my ruling. there will be no further discussion on this.

(iv) मुख्यमंत्री के भाई द्वारा कथित जमीन हड़पने सम्बन्धी

प्रोफ़ेसर सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैं उस समय जो मैंने बोल गया था, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने जो अपनी काल अटैन्शन मोशन दी है उसके अन्दर मैंने लिखा है कि मुख्य मंत्री के भाई ने वहाँ पर 10 करोड़ रुपये की जमीन हड़प ली है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: अभी तक आपकी काल अटैन्स इन मोशन मेरे पास आई नहीं हैं जब आयेगी तो उस समय उसको देख लूंगा। (गोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, अभी इन्होंने कहा है कि मेरे भाई ने कुछ जमीन हड़प ली है। ये सरासर गलत कह रहे हैं। यदि इनकी यह बात सच हो तो मैं अस्तीफा दे दूंगा वरना यह इस्तीफा दे दें। (गोर)

प्रोफ़ेसर सम्पत सिंह: मैं आपका चैलेन्ज ऐक्सैप्ट करता हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप पहले काल अटैन्स इन मोशन का फ़ैसला तो होने दें। (गोर)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, ये सब लोगों को देवी लाल की तरह समझते हैं। सब लोगों को ऐसा ही समझते हैं जैसे औम प्रकाश काम किया करता था, या जैसे यह खुद किया करता है। (व्यवधान) अगर जमीन को हड़पने की बात साबित कर दे तो मैं आज ही यहां से इस्तीफा दे दूंगा। (व्यवधान)

Shri Verender Singh: Sir, he is threatening the member. How can he do so? (Interruptions)

श्री मंगल सेन: स्पीकर साहब, मैं आपसे एक सबमिशन करना चाहता हूँ। हमारे मुख्य मंत्री जी जरा टच्ची हो गये हैं और नाराज हो गये हैं। इनका कहना है उनके भाई ने कोई भी जमीन

अलाट नही करवाई हैं। कोई नाजायज काम नही करवाया हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी फ़ैयरनैस के लिए हाउस की एक कमेटी बना दें ताकि इस बात का फ़ैसला हो जाए।(व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ। यह भी इस्तीफा दे दें, मैं भी लिखकर इस्तीफा दे देता हूँ। यह क्या बात करते हैं।(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: दोनों ही इस्तीफा दे दें। आप इन्क्वायरी कमेटी बनाये, आप भी इस्तीफा दिलवा देंगे।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप थोड़ा से डैकौरम रखें। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर अनफ़ांअडिड बातें कहनी भुरू हो जाएं जिनका कोई सिर-पैर न हो तो अच्छी बात नहीं हैं। परसों भी श्री लछमन सिंह कम्बोज ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के भाई ने जमीन ले ली। मैं भी करनाल का रहने वाला हूँ। मैं उस गांव को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर बात के पीछे कुछ फ़ैक्ट्स हों तो आप जरूर कहें, किसी को स्पेयर न करें।(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: ये थ्रैट कर रहे हैं। ये कैसे थ्रैट कर सकते हैं?(व्यवधान) ये थ्रैट नहीं कर सकते, एलीगै इन को रिफ़्यूट कर सकते हैं।(व्यवधान) क्या आपके सामने ये किसी मैम्बर को थ्रैट कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, इस मसले को हल करने के लिए आप हाउस की एक कमेटी-अप्वायंट कर दीजिए, फैसला हो जाएगा? (व्यवधान)

Mr. Speaker: Please take your seat. No further discussion on this matter, please. Now the Revenue Minister will make a statement on Call Attention Motions.

प्वायंट आफ आर्डर

श्री किताब सिंह, एम0एल0ए0 की कथित अवैध गिरफ्तारी आदि के तथ्य की तहकीकात करने के लिए सदन की एक समिति की नियुक्ति का सूझाव

श्रीमति चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर स्पीकर साहब, आपने मुझे उठने भी नहीं दिया और एजेंडे की दूसरी आइटम भुरु कर दी। इससे पहले मैं तीन-चार बार बोलने के लिए खड़ी हुई थी।(व्यवधान) जनाब, श्री किताब सिंह एम0एल0ए0 को पुलिस द्वारा पीटने की बात अभी तक लटक रही हैं, इसका जवाब अभी तक नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्रीमति चन्द्रावती: अगली बात यह है जनाब कि मैंने एक काल अटैन्-ान मो-ान दिया हुआ है। जिसमें श्री हुकम सिंह के भाई की बाबज जो इल्जाम लगाया हैं। उसके खिलाफ 62 गावों

की पंचायत हुई थी और यह पंचायत कौसली गांव में हुई थी और यह पंचायत कोसली गांव में हुई थी जिसने एक रैजोल्यूशन भी पास किया था। ढानी फोगट गांव का एक रामचन्द्र नाम का आदमी, जिसका ट्रैक्टर जला दिया गया।.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभी यह काल अटैन्डान्स में आने के लिए पास नहीं आई, जब आ जायेगी तो मैं कंसीडर करूंगा।

श्रीमति चन्द्रावती: ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि हमें चैम्बर में आवासन दिया था कि लैंड ग्रैबिंग वाला मामला पर एक कमेटी मुकर्रर करेगी।

श्री अध्यक्ष: मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कहा था सोचें।(व्यवधान)

श्रीमति चन्द्रावती: आपने सोचा है या नहीं?(व्यवधान) यह जो लैंड ग्रैबिंग के मामले वाली बात है इसके लिए एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाए ताकि मुख्य मंत्री जी अपनी सफाई दे सकें। इसके अलावा जनाब, श्री किताब सिंह वाली बात के बारे में आपने क्या सोचा है।(व्यवधान)

Mr. Speaker: I have disallowed it.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हमने नम्रता के साथ आपसे निवेदन किया था और आपने सोचने के लिए कहा था। यह एक ऐसा मामला है जिसमें मैम्बरज के राइट्स इन्वाल्ड है क्योंकि

एक एम0एल0ए0 के साथ एन्क्रोचमेंट आफ राईट्स हुआ हैं। इसमें इनको एतराज नहीं होगा इसलिए हाउस की एक कमेटी बना दी जाए। ठीक हैं, प्रिविलिज मौं इन तो आपने रिजैक्ट कर दी, लेकिन कम से कम एक कमेटी बना दी जाए जिसमें दो मैम्बर कांग्रेस पार्टी के हो ओर एक मैम्बर हमारा हो जाए ओर यह कमेटी आन दी स्पौट स्टडी करके अपनी फाइंडिंग दे दे।

श्री अध्यक्ष: मैं सुबह ठीक 8 बजे यहां दफतर में पहुंच गया था क्योंकि इस सिलसिले में मैंने एडवोकेट जनरल और एल0आर को बुलाया हुआ था। हमने इस प्वायंट पर सारी किताबे पढ़ी हैं, और देखी है और उनसे डिसक्स किया हैं ताकि कोई वे-आउट निकाला जा सके लेकिन इसके साथ ही साथ जहां आप मैम्बर साहिबान अपने राइट्स को महसूस करते हैं वहा मेंरी भी एक जिम्मेदारी हैं। मै किताबों में जो प्रोसीजर ले-डाउन किया हुआ हैं, उससे बाहर नहीं जा सकता। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने इसकों डिसअलाऊ कर दिया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हम इसको रिव्यू करने के लिए परसिस्ट नहीं कर रहे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात प्रोसीजर और ला की है। इसमें फ़ैक्ट्स की बात नहीं हैं। फ़ैक्ट्स की बात होती तो मै यह मामला कमेटी को भेज देता लेकिन इस केस में फ़ैक्ट्स की बात नहीं हैं। ला एंड प्रोसीजर की बात हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह इंसिडेंट्स है या नहीं, इसका रैफ्रेंस तो दे दें।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं फैक्ट्स के ऊपर कुछ नहीं कहता। मैंने ला एंड प्रोसिजर के ऊपर रिजैक्ट किया है। इस में कमेटी क्या करेगी?(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं आप से यह कह रहा हूँ कि a committee be constituted to find out the truth in the incident.

श्री अध्यक्ष: मैं आपको बार-बार यही समझा रहा हूँ कि मैंने फैक्ट्स के ऊपर नहीं बल्कि आने दी बैसिंज आफ दी प्वायंट आफ ला एंड प्रोसिजर के इसका डिसअलाऊ किया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, प्रिविलिज मो इन तो आपने रिजैक्ट कर दी ठीक है, लेकिन अब एक कमेटी तो कांस्टीच्यूट कर दे ताकि वह कमेटी इन फैक्ट्स पर अपनी फाइंडिंग दे। We are not persisting on this motion. We are saying that under the Rules of Procedure and Conduct of Business you have got sample powers to appoint an independent Committee to find out whether the allegations which the member has levelled are correct or not. This will be the scope of that committee and we will be satisfied.

श्री अध्यक्ष: फर्ज करो मैं दो एम0एल0एज0 की कमेटी बना देता हूँ और वह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दें तो what action can be taken on that report?

Shiri Verender Singh: You can take cognizance of this Report and I can satisfy you about it.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहबए कल हमने आपसे प्रार्थना की थी और आपने इस बात को स्वीकार करके हम पर कृपा की थी इस बात पर सोचेंगे। इस सिलसिले में आपने एडवोकेट जनरल और लीगल रिमेंबरेंसर को कंसल्ट करने के लिए आज सुबह बुलाया। स्पीकर साहब, हमारा कंसरन इस में है और बार—बार आपसे रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि एक कमेटी बना दी जाए। हमारी डिगनिटी और डैकोरम को प्रोटैक्ट करने वाल आप ही हैं। आपके होते हुए एक मैम्बर को टारचर किया जाता है और इस सूबे से बाहर ले जाया जाता है, यह कितनी गलत बात है। यह ठीक है अरैस्टस होती है, रोज होती है लेकिन एक स्टेट दूसरी स्टेट में ले जाना, और उसको पे गाब भी न करे देना कितनी गलत बात है। पे गाब न कराने की वजह से उसको होस्पिटल में दाखिन होना पड़ा। स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल जी ने जेल नहीं देखी, इसी लिए रूल्ज आफ प्रोसीजर क्रिएट भी किए जा सकते हैं। आपके पास पावर्ज हैं, इन पावर्ज को इस्तेमाल करते हुए और आपके इन्साफ के रास्ते पर अगर कोई रूकावट हो, तो आप उसको स्वये दूर कर सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसका स्वीकार कर लें।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब हम आपको बार—बार कश्ट दे रहे हैं। आप हमारी बात पर जरा गौर फरमायें। हम

आपसे केवल यह गुजारि 1 कर रहे हैं कि मैम्बर को बापके सिवाए कोई भी प्रोटैक 1न नहीं दे सकता। जैसा चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि आप हाउस के मैम्बरान की एक कमेटी को अप्वायंट करें, उस कमेटी को अप्वायंट करना आपके स्कोप में हैं। आपको ही अधिकार हैं। पहले आप उस मैम्बर की स्टेटमेंट ले लें, उसकी बात सुन लें। आप नये सिरे से इस बारे में गौर करके कम से कम उसकी बात तो सुन ले। (गोर)

श्री अध्यक्ष: यह तो आपकी बात ठीक है लेकिन यह एक बैड प्रेसिडेंट होगा कि पहले तो मैं किसी बात को डिस-अलाऊ करूँ और बाद में फिर उसे ही कन्टीन्यू कराऊँ। यह अच्छा नहीं लगता।(गोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, क्या यह अच्छा लगता है कि एक विधायक को इस प्रकार से पीटा जाये और आप उस पर गौरप न फरमाये। इस तरह से काम नहीं चल सकता।(गोर)

Mr. Speaker: No More discusstion now. I am very sorry that मैंने बड़ी नमी से ओर बार-बार सोच कर यह फैसला दिया है हालांकि मैं इसे उस दिन भी डिस अलाऊ कर सकता था। (गोर) आपने पहले दिन वाक आउट भी कर लिया लेकिन फिर भी आपकी बात मान कर दोबार मैंने लीगल ल्यूमनरीज को कंसल्ट किया। सोरे केस को दोबारा स्टडी किया। अगर अब भी आपका कन्डक्ट यही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ।

श्रीमती चन्द्रावती: आपको कन्डक्ट वाली बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम आपके सामने अपनी सामने अपनी बात न कहें तो और किस के सामने कहें। गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। आपसे हमारी यही गुजारि है कि फ़ैक्ट फ़ाईडिंग कमेटी मुकर्रर कर दें। हमारी तरफ से भी एक मैम्बर ले ले और रूलिंग पार्टी की ओर से दो मैम्बर ले लें ताकि फ़ैक्टस का पता लग सके।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिए, मैं इसे डिस अलाऊ कर चुका हूँ। (व्यवधान) आप बराय मेहरबानी अपनी सीटों पर बैठ जाईये I have decided it once for all. I will not open this chapter again now.

(इस समय चौधरी किताब सिंह आपेजी इन के बैन्चिज के फॉर पर बैठ गये)

Revenue Minister (Chaudhri Phool Chand): Sir, I think they are not particular about any call attention motion and they are not serious to hear the statement that i have been asked to make.

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जिस आदमी को पीटा गया है कम से कम उसकी बात तो सुनिए।(गोर)

श्री अध्यक्ष: बहिन जी, मैंने सारी पार्टी के मैम्बरान की बात सुन ली है और वह भी एक बार नहीं दो दफा सुनी है।

दूसरी बात यह है कि जब मैंने रूलिंग दे दी तो फिरप आप उसी बात को लेकर खड़े हो जाते हैं। क्या स्पीकर की रूलिंग को चैलेन्ज नहीं है। (गोर) किताब सिंह जी को समझाइये कि व अपनी सीट पर बैठें। (व्यवधान व गोर)

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब, हम आपकी रूलिंग को चैलेन्ज नहीं कर रहे हैं। एक एम0एल0ए0 को अपनी बात कहने का तो हक है। उसकी बात तो आपको सुननी चाहिए। (इस समय कई मैम्बर खड़े हो कर बोलने लग गये जो रिकार्ड न किया गया।)

श्री अध्यक्ष: यह कोई भी बात रिकार्ड नहीं करनी है। (गोर)

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरी आपसे एक सबमिशन है कि किताब सिंह को टोरयर किया गया, पीटा गया। कम से कम एक बार आप उनकी बात तो सुन ले। (गोर)

श्री अध्यक्ष: पहले आप किताब सिंह को अपनी सीट पर बिठाईये। (व्यवधान व गोर)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपने वाजह फरमाया कि आपने एक बार नहीं, दो-तीन बार रूलिंग दे दी। आपने हमें चैम्बर में भी सुना लेकिन उसके बावजूद भी एम0एल0ए0 एजिटेटिड है। इसलिए आपको हमारी कुछ नाराजगी को भी समझना चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने तो पुलिस को लाईसेंस दे दिया है कि जिस एम0एल0ए0 को चाहें ह्यूगमिलेट कर दे। इस तरह से ह्यूमिलेट

हो कर कोई भी एम० एल० ए० असैम्बली में बैठनक के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आप जिस ढंग से हाउस को चला रहे हैं वह काबिले तारिफ हैं।

(इस समय चोधरी किताब सिंह अपनी सीट पर जा कर बैठ गये)

वक्तव्य—

राजस्व मंत्री द्वारा सूखे तथा ओलावृष्टि के कारण हुई हानि के लिए मुआवजा देने सम्बन्धि

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने श्री निहाल सिंह श्री हीरा नन्द आर्य तथा श्री राम विलास भार्मा के काल अटैन्डान नोटिसिज पर स्टेटमेंट देने के लिए कहा था। इसलिए अब रैवेन्यू मिनिस्टर साहब अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं।
(व्यवधान)

Revenue Minister (Chaudhri Phool Chand): As per standing practice the damage is being assessed by means of girdawari and on completion of the same the actual quantum of loss will be known whereafter relief by way of Suspension/ Remission of land Holdings tax and abiana deferment of loans and other assistance will be considered keeping in view the past practice in this regard.

Ten villages of Nangal Chaudhry block, Tehsil Narnaul, District Mahendragarh were affected by hailstorms on 24.02.1983 in varying degrees. It is, therefore, incorrect to

say that the entire rabi crop in this block has been destroyed by hailstorms. No Hailstorms are reported to have occurred on 24.01.1983 in district Mahendragarh. A total of 47 villages were affected by hailstorms in Bhiwani District on 24.02.1983 including Alampur and Kural. Similarly between January and March to-date nine villages in Hissar District and four villages in Kurukshetra district are also reported to have been affected.

प्वायंट आफ आर्डर

श्री किताब सिंह एम0एल0ए0 की कथित अवैध गिरफ्तारी आदि के तथ्य की तहकीकात करने के लिए सदन की एक समिति की नियुक्ति सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

11.00 बजे

श्री मंगल सैन: * * * * * *(व्यवधान व भाोर)* * * * *
** *(व्यवधान व भाोर)..... वैसे तो आपका वे आफ कंडक्टिंग दी हाउस बड़ा एप्रीं एबल हैं। आपने तसे हर मामले में कमाल कर दिया। मेरी आपसे सबमी तन है कि आप इनके ऊपर प्रिवेल अपौन कीजिए। आप इनको समझाइयेगा कि इनाक क्या बिगड़ता हैं। जो पुलिस वाला इनको हरियाणा से बाहर ले गया था, क्या वह इनके कहने पर ले गया था। अगर इनके कहने पर नहीं ले गया था, जो उसको सजा देने में क्या एतराज है।(व्यवधान व भाोर) उसके विरुद्ध एक तन लेने में इनको क्या एतराज

हैं। (व्यवधान व भाोर) इस बारे में आप तथ्य जानने के लिए हाऊस की एक कमेटी नियुक्त कर दें।

श्री अध्यक्ष: आप फिरप वही मामला रेज़ करप रह हैं जो क्लोज हो चुका हैं मैंने कल आपका सारी डिटेल में बता दी थी। इसलिए मैं आपसे यह बार-बार कह रहा हूँ कि आप यहां का जो डैकोरम तथा जो प्रोसीजर हैं, उसको भंग न करें। मेरी सिम्पथी सदा ही अपोजि उन के साथ हैं और वह तभी जारी रह सकती हैं अगर आप मुझे कोओप्रेट करेंगे अगर आप इसी किस्म का माहोल पैदा करेंगे तो I shall have to be strict according to the procedure. अब तक तो मैंने आपको ट्रैजरी बैंचिज से भी ज्यादा टाईम दिया हैं और आपकी बात को मान कर चल रहा हूँ।

Shrimati Chandrawati: This is so good of you, Sir.

श्री अध्यक्ष: लेकिन यह माहौल जो आज आपने क्रिएट किया हैं, यह दिखाकर आप मुझे मजबूर करते हैं कि I should go according to this book. I would request you again not to create such an atmosphere. मैंने जो रूलिंग दी हैं वह अटल है ओर फाईनल हैं। I will not change it and i am very sorry for that.

श्री कंवल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, आप हमारी बात सुन तो लिजिए (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: Please sit down. I will not listen anything which is not relevant. (Interruption and Noice). No further discussion will be allowed on this subject.

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, आपने कहा था कि आप किताब सिंह को बोलने के लिए समय देंगे। (व्यवधान व भाोर) आपने यह कहा था कि इनको आप सीट पर बिठा दें, मैं इनको इजाजत दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं इनको वक्त दूंगा मैंने तो यह कहा था कि आप इनको सीट पर बिठाईये। आप से मैंने यह नहीं कहा था कि मैं इनको बोलने के लिए वक्त दूंगा।

श्रीमती चन्द्रावती: * * * * * (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: There will be no more discussion on this subject.

वक्त्वय

राजस्व मंत्री द्वारा सूखे तथा ओलावृष्टि के कारण हुई हानि के लिए मुआवजा देनें सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now, the Hon. Revenue Minister may please resume his statement.

Chaudhri Phool Chand: Sir, I have already read out the Statement upto para 2. It further reads—

3. Geographically Haryana is situated in an area which is prone to hailstorms at this time of the year. Hailstorms tend to occur throughout the State from about the

3rd week of February upto the 1st week of April, thereby affecting the maturing Rabi crops. This fact is borne out by the occurrence of hailstorms at approximately the same time of the year for the last three to four year during which a large amount of gratuitous relief has been paid.

4. Under the circumstances the full picture of damage, whether in Nangal Chaudhary block or for the State as whole will only emerge after the girdawari is over and the crops are ripe for harvesting. It would not be desirable for Government to proceed in the matter of affording compensation for crops damaged in a piecemeal manner since a policy decision has to be taken for the State as a whole.

(b) DROUGHT

5. The late on-set and early withdrawal of monsoons during the Kharif 1982 season resulted in drought condition in 7 districts of the State, namely, Hissar, Bhiwani, Gurgaon, Faridabad, Rohtak, Mahenderagarh and Jind. This was the fourth consecutive drought during Kharif season in many parts of these districts and the crop loss resulted in much hardship to the farmers.

6. The lack of soil moisture in the rain-fed area of the State affected the Rabi sowings to the extent that there was shrinkage in area particularly under gram crop. In order to improve sowing conditions at the beginning of the Rabi season water was diverted from the Western Yamuna Canal and Bhakra System to the Lift-Irrigation System to bring large areas under gram and oilseeds in the south western district. (Interruptions & Noise) similarly the electricity supply to

tubewells was raised to 10 hours daily by redacting to it 6 hours in districts such as Karnal and Kurukshetra.

सस्पैं इन आफ सिंटिंग

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। देखिये जनाब, हरियाणा को आप यू0पी0 मत बनने दीजिए। वहा तो एम0एल0ए0 को भूट कर दिया जाता हैं। हम तो केवल यह चाहते हैं कि आगे से कोई भी एल0एल0ए0 के ऊपर हाथ न उठाने पाए। (व्यवधान व भाोर)।

श्री अध्यक्ष: आप कौन से रूल के मुताबि बोल रही हैं।

Chaudhri Phool Chand: This point does not arise out of the statement, Sir. (Interruption & Noise)

श्रीमती चन्द्रावती: सर मैं प्वायंट आफ आर्डर,पर बोल रही हूं। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि श्री किताब सिंह एम0एल0ए0 को पीटा गया हैं। (व्यवधान व भाोर) * * * * * (व्यवधान व भाोर)।

श्री अध्यक्ष: मुझे बड़े अफसौस के साथ यह कहना पड़ रहा हैं कि मंत्री महोदय काल अटैन् इन मो इन का जवाब दे रहे हैं और आप लोग यहां पर भाोर मचा रहे हैं।(व्यवधान व भाोर)

श्रीमती चन्द्रावती: सर, आपको हमारी बात सुननी चाहिए। हम आपके पास अगर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए

नही आएंगे तो किसके पास जाएंगे।(व्यवधान व भाोर) * * * * *
(व्यवधान व भाोर)।

Mr. Speaker: Hon'ble Revenue Minister may please resume the statement.

Chaudhri Phool Chand: Similary, the electricity (Noise and Interruptions).

(At this stage Shri Kanwal Singh and some other Members of the Opposition again started speaking without permission on the again of Shri Kitab Singh M.L.A. and there was great noise and when asked by the Chair to resume their seats, they did not do so. Rather some of them came and sat near the Table of the House).

Mr. Speaker: The House is adjourned for 15 Minutes.

(The Sabha then adjourned for 15 minutes and re-assembled at 11.24 a.m.)

वक्त्वय

राजस्व मंत्री द्वारा सूखे तथा ओलावृष्टि के कारण हुई हानि के लिए मुआवजा देने सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Hon'ble Revenue Minister any please resume his statement.

Chaudhri Phool Chand: I have already read out the statement upto paragraph 6. Now i will start from paragraph 7.

7. My Government is fully conscious of difficult conditions prevailing in the south-western districts of the State particularly Bhiwani, and Mahendragarh and our heart-felt sympathies are with the farmers. In order to tackle this situation, a comprehensive memorandum was presented to the Government of Indian for advance planed assistance and I am happy to state that they have given an assistance of Rs. 11.82 crores for meeting this difficult situation. Out of this, an additional provision of Rs.2.39 crores has been made for subsidising agricultural inputs for small and marginal farmers, Rs.2.53 crores for drinking water supply in problem villages, Rs.2.87 crores for extending irrigation facilities in drought affected area, Rs.2.25 crores for the conversion of shout-term co-operative loans into medium-terms loans and Rs.1.28 cores for roads and other village-level works and Rs.50 lakhs for safe-guarding animal health. besides this, the State Government has also issued instructions for the suspension/remission of land holding tax and abiana on the basis of 'Kharaba"recorded in the 'girdawari'

8. I would like to take this opportunity to assure the house that every possible efforts is being made by the State Government to alleviate the sufferings of the area affected during the previous Kharif. We are really fortunate that timely and abundant rain-fall from late December has

materially brightened the Rabi prospects and many farmers who were unable to sow gram, have been able to go in for late varieties of wheat.

9. I may again assure the House that the situation will be closely watched and whatever further assistance is required will be made available on top priority basis.

चौधरी मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, अक्सर लोगों की यह शिकायत रहती है कि जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो हिन्दी में वोट मांगते हैं और हाउस में अंग्रेजी बोलना आरम्भ कर देते हैं और आम लोगों को अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसका हिन्दी में भी पढ़ा जाए।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, स्टेटमेंट हिन्दी में पढ़ दें।

(क) ओलावृष्टि

1. जिला महेन्द्रगढ़ की तहसील नारनौल के ब्लॉक नागल चौधरपी के 10 गांव दिनांक 24.02.1983 को हुई ओलावृष्टि से विभिन्न स्तरों तक प्रभावित हुए। अतः यह कहना गलत है कि इस ब्लॉक में ओलावृष्टि से तमाम रबी की फसल नष्ट हो गई है। जिला महेन्द्रगढ़ में दिनांक 24.01.1983 को ओलावृष्टि की रिपोर्ट नहीं है। जिला भिवानी में दिनांक 24.02.1983 को हुई ओलावृष्टि से आलमपुर व कुराल सहित कुल 47 गांव प्रभावित हुए थे। इसी प्रकार मास जनवरी से मार्च तक जिला

हिसार के 9 गांव तथा जिला कुरुक्षेत्र के चार गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं।

2. चालू प्रथा के अनुसार गिरदावरी द्वारा नुकसान आंका जा रहा है तथा इसके पूर्ण होने पर नुकसान की वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा जिसके पचास लैंड होल्डिंग टैक्स के निलम्बन/मुआफी, ऋण वसूली स्थगन तथा अन्य सहायताओं द्वारा राहत देने बारे पूर्व प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

3. भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां वर्षा के इस समय में प्रायः ओलावृष्टि होती रहती है। फरवरी के तीसरे सप्ताह से लेकर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक ओलावृष्टि की सारे राज्य में होने की सम्भावना बनी रहती है जिससे पकती हुई रबी की फसल पर प्रभाव पड़ सकता है। पिछले तीन चारप वर्षों में वर्षा के लगभग इस ही समय में होनी वाली ओलावृष्टि को देखते हुए इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है जिसके लिये काफी धनराशि राहत के रूप में दी गई है।

4. ऐसी परिस्थितियों में नुकसान का पूरा नक आ चाहे यह नागल चौधरी ब्लॉक का हों, चाहे सारे राज्य का तभी स्पष्ट हो सकता है जब गिरदावरी पूर्ण हो जाए और फसलें कटने हेतु पक जायें। यह सरकार के लिये उचित नहीं होगा कि बार-बार

आणि एक रूप में अनुदान देने हेतु कार्यवाही करें क्योंकि सारे राज्य के लिये एक ही नीति निर्धारित करनी पड़ती है।

(ख) सूखा:

5. खरीफ 1982 के समय वर्षा के देर से आरम्भ होने तथा भीघ ही समाप्त हो जाने के फलस्वरूप राज्य के सात जिलों हिसार, भिवानी, गुड़गाव, फरीदाबाद, रोहतक, महेन्द्रगढ़ तथा जीन्द में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन जिलों के कई भागों में यह खरीफ में निरन्तर पड़ने वाला चौथा सूखा था और फयलों को हानि होने से किसानों को काफी कठिनाइयां हुईं

6. राज्य के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में भूमि में नमी की कमी के कारण रबी की फसल विशेषकर चनों की फसल के बीजाई के क्षेत्र में कुछ सीमा तक कमी आई है। रबी की फसल की बीजाई के समय, बीजाई की स्थिति सुधारने के लिये, ताकि दक्षिण पश्चिमी यमुना नहर तथा भाखड़ा सिस्टम को पानी लिफ्ट सिंचाई स्कीम में डाल दिया गया। इसी प्रकार करनाल तथा कुरुक्षेत्र जैसे जिलों में बिजली सप्लाई में कटौती करके 6 घंटे प्रतिदिन की गई ताकि इन क्षेत्रों में ट्यूबवैलों को प्रतिदिन 10 घंटे बिजली उपलब्ध की जा सके।

7. मेरी सरकार राज्य के दक्षिण पश्चिम विशेषकर भिवानी तथा महेन्द्रगढ़ जिलों की कठिन स्थित के बारे में पूर्ण रूप से जागृत है तथा हमारी हार्दिक सहानुभूति किसानों के साथ

हैं। इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार को अग्रिम योजना सहायता हेतु एक विस्तृत ज्ञापर प्रस्तुत किया गया था और मैं यह कहने में प्रसन्नता अनुभव करता हूँ कि उन्होंने हमें इस कठिन स्थिति से निपटने हेतु 11.82 करोड़ रुपये की सहायता दी है। इसमें से लघु तणि सीमान्त किसानों को सस्ते भाव पर फर्टीलाइजर आदि उपलब्ध करवाने हेतु 2.39 करोड़ रुपये को अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, समस्या-गावों में पीने के पानी की योजनाओं के लिए 2.53 करोड़ रुपये, सूखग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु 2.87 करोड़ रुपये, अल्प-अवधि सहकारिता ऋण को मध्यम-अवधि ऋण में बदलने हेतु 2.25 करोड़ रुपये, सड़को तथा गांव-स्तर कार्यों के लिये खर्च कार्यों के लिए रुपये 1.28 करोड़ तथा 50 लाख रुपये पशुओं के स्वास्थ्य आदि पर खर्च के लिये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने गिरदावरी में दिखाए गए खराबा के आधार पर लैंड होल्डिंगज टैक्स तथा आबियाना के निलम्बन मुआफी के लिये हिदायतें जारी कर दी हैं।

8. मेरे सदन को इस अवसर पर विचार वास दिलाना चाहूंगा कि पिछली खरीफ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कष्टों के निवारण हेतु सरकार हर सम्भव कोशिश कर रही है। हम भाग्यशाली हैं कि दिसम्बर के अन्त समय पर और काफी मात्रा में वर्षा होने के कारण रबी के उत्पादन में काफी सीमा तक सुधार हुआ है तथा कई किसान जो चने की फसल की बुआई

करने में असमर्थ रहें, गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्म की बीजाई करने में सफल हुए हैं।

9. मै पुनः इस सदन को वि वास दिलाता हूं कि स्थिती का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा तथा जिस प्रकार की सहायता की आव यता प्रतीत हुई, परम अग्रता के आधार पर दी जाएगी।

श्री हीरा नन्द आर्य: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछली बार जो ओलावृष्टि से किसानों का नुकसान हुआ था उसका सारा मुआवजा दे दिया गया है? स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि पिछले चार पांच साल से कुछ हिस्सों में कहत पड़ता आ रहा है मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन एरियाज में सरकार तकावी लोन वगैरह राइट आफ करने के बारे में विचार करेगी क्योंकि वे लाग लोन वापिस करने की स्थिती में ही नहीं हैं?

चौधरी फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, माननीय मैम्बर ने पूछा है कि पिछली बार जहां पर औले पड़े थे क्या वहां पर मुआवजा बांटा गया है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष ओलावृष्टि से क्षति के कारण जो जिलों से मांग आई थी वह कूल 14 करोड़, 5 लाख, 84 हजार 360 रूपये थी और सरकार ने 12 करोड़, 36 लाख, 37 हजार 925 रूपये डिप्टी कमि नर्ज की डिस्पोजल पर रखे थे। इसमें से काफी रूपया तो बांट दिया गया है लेकिन कई कारणों की वजह से

जैसे कोई आदमी नहीं मिला, कई दफा कोई झगड़ा होता है 69 लाख, 15 हजार 279 रूपया देना बकाया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सूखे का सम्बन्ध है, उस बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के आकड़ें सरकार को उपलब्ध होते हैं, उसी के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है। इस बारे में काफी केस डी0सीज0 के पास अनडिसपोज्ड पड़े हुए हैं। वैसे गिरदावरी के आदेश भी दे दिये गये हैं, इससे यह देखा जा सकता है कि किस-किस का कितना-कितना और कहां-कहां नुकसान हुआ है। कर्जा माफी को जह्य तक ताल्लूक है, सरकारी तौरप पर जहां कहीं सूखे की स्थिति हो जाती है, वहां पर उसकी वसूली की अवधि बढ़ा दी जाती है और लेण्ड रैवेन्यू माफ कर दिया जाता है। ऐसी हिदायतें सरकार की तरफ से दी गयी हैं। एक तो सूखा पड़ा और दूसरा बरसात न होने के कारण हालाज बहुत खराब हो गये जिसके कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारी सहानुभूति किसानों के साथ है। इसी कारण से बरबादी वाले इलाकों में लोगो को काफी राहत दी गयी है और दी जा रही है।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने काल अटैन् इन नोटिस के द्वारा सरकार के नोटिस में यह बात लाई थी कि 24.01.1983 को महेन्द्रगढ़ जिले के कुछ गांव सैलांग, अकौदा, नोटाना, पोटा सयाना, बस्सी और खेरपी वगैरह में औलावृष्टि से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है लेकिन मंत्री महोदय ने अपने

जवाब में यह बताया कि जिला महेन्द्रगढ़ में दिनांक 24.01.1983 को औलावृष्टि से तमाम रबी की फसल नष्ट हो गयी है। मैं आपके द्वारा इनसे यह पूछना चाहता हू कि इन्होंने किस बिनाह पर यह कह दिया कि महेन्द्रगढ़ जिले के इन गावों में औलावृष्टि के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है?

चौधरी फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में यह कहा है कि जिला महेन्द्रगढ़ की तहसील नारनौल के ब्लाक नांगल चौधरी के 10 गांव दिनांक 21.01.1983 को औलावृष्टि से विभिन्न स्तरों तक प्रभावित हुए। अतः यह कहना गलत है कि इस ब्लाक में औलावृष्टि से तमाम रबी की फसल नष्ट हो गयी है। जिला महेन्द्रगढ़ में दिनांक 24.01.1983 को औलावृष्टि की कोई रिपोर्ट नहीं है, फिर भी हमने वहां की गिरदावरी के आदे 1 दे दिए हैं जहां कहीं भी नुकसान का मामला ध्यान में आएगा वहां पर हम लोगों को पूरा मुआवजा देंगे।

श्री निहाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने बताया कि जहां-जहां ऐसा नुकसान हुआ है, वहां के लोनज सस्पेंड किए जाएंगे और उनमें आगें के लिए मुतलवी किया जाएगा। मैं इन से यह पूछना चाहता हू कि जो को-आपरेटिव लोनज हैं क्या उनको भी सरकार सस्पेंड करने का विचार रखती है?

चौधरी फूल चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि जो भारत टर्म लोनज हैं, उनको इसी क्षेत्र में सरकार ने मिडियम टर्म लोनज में कंवर्ट कर दिया है और इसके अलावा और भी राहत के कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि खराबा के आधार पर आबयाना की मुआफी के लिए हिदायतें जारी कर दी हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, कई ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने नहर के पानी की बजाए अपने ट्यूबवैल के पानी से खेती की हो और उनकी फसल भी औलावृशिट या दूसरे कारणों से 50 प्रति ात से अधिक खराब हो गयी है। चूंकि ऐसे किसानों को अपने ट्यूबवैल-चलाने की वजह से लगभग 10 गुणा बिजली का काफी खर्चा पड़ा है, क्या दूसरे किसानों की तरह बिजली के बिलों की अदायगी से माफी दी जाएगी? क्या ऐसी स्कीम सरकार के विचाराधीन है?

चौधरी फूल चन्द: स्पीकर साहब, ऐसी कोई सरकार की नीति नहीं है, हम तो केवल मालिया ही माफ कर देते हैं।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से रैवन्यू मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि किसानों को जो नुकसान का मुआवता दिया जाता है, वह किस क्राइटेरिये को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है? किस परसैन्टेज के हिसाब से

दिया जाता है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि साथ में पंजुओं के चारे के बारे में सरकार क्या करने जा रही है?

चौधरी फूल चन्द: स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर साहब को यह बाताना चाहता हूँ कि जहाँ पर 75 परसेन्ट या इससे ज्यादा का नुकसान होता है, वहाँ पर हम 400 रूपय प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देते हैं। जहाँ पर 50 से 75 के बीच नुकसान होता है, वहाँ पर हम किसानों को 300 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से और जहाँ 25 से 50 परसेन्ट तक नुकसान होता है, वहाँ पर हम 200 रूपय प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देते हैं लेकिन इससे नीचे जिसका नुकसान होता है, उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। जहाँ तक चारे का सम्बन्ध है, चारे के बारे में कोई ऐसी रिपोर्ट आएगी तो हम कृषि विभाग वाले मिलकर सहायता करेंगे।

गैर सरकारी संकल्प

जिला अम्बाला की तहसील अम्बाला को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Now the House will take up the non-official resolutions और श्री रामदास धमीजा अपना रेजोल्यूशन मूव करेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, अभी चैम्बर में आपसे जो हमारा बात हुई है, उसके बारे में आप कुछ अनाउंस करने वाले थे।

श्री अध्यक्ष: मैं अनाउंस करूंगा।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला कौन्ट): स्पीकर साहब, मैं अपना प्रस्ताव मूव करता हूँ।

कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि अम्बाला जिले की अम्बाला तहसील को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जाए।

स्पीकर साहब, अब मैं इस बारे में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ कि अम्बाला जिले की अम्बाला तहसील को बैकवर्ड एरिया करार क्यों दिया जाए? जो इंडस्ट्री मौजूदा हैं, उनकी हालत काफी खस्ता है क्योंकि वहाँ पर सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटीज नहीं दी गयी हैं। वैसे अम्बाला जिला इकनामीकली भी काफी बैकवर्ड है क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज तरककी नहीं कर रही हैं। भारत सरकार ने बहुत सी इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरियाज के लिए मकसूस कर रखी हैं और उन्हें दूसरे एरियाज में बैन कर रखा है। अगर अम्बाला तहसील को भी इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरियाज की लिस्ट में शामिल कर लिया तो हम भी भारत सरकार सेकी इस नीति का फायदा उठा सकते हैं। भारत सरकार के इस बैन से हमारी अम्बाला तहसील को काफी

नुकसान हो रहा है, इसलिए अम्बाला तहसील की इकनमिक पोजी उन को ऊपर उठाने के लिए हरियाणा के दूसरे जिलों की तरह अम्बाला तहसील को भी इंडस्ट्रीयली बैक्वर्ड करार दिया जाए। इलैव उन से पहले सरकार ने दस इलाके के बारे में यह तसल्ली भी की थी कि अम्बाला कैंट और साथ के बैक्वर्ड एरियाज के लिए इंडस्ट्रीज को ऊपर उठाने के लिए लोगों पको रियायतें देंगे, स्कीमज पेरी करेगें लेकिन वह फायदा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 31 मार्च को जो ऐसे कामों के लिए फन्डज दिए जाते हैं, वे काफी लेट दिए जाते हैं जिससे इस तरह के काम होने में सरकार की तरफ से काफी देरी हो जाती है।

अम्बाला में सिर्फ एक साईस इंडस्ट्री ही ऐसी है, जिसका सामान सारे भारत में सप्लाई किया जाता है और स्कूलों में अगर सरकार की तरफ से फन्डज वगैरह सही समय पर दे दिए जाएं तो स्कूल वहा से अपना माल समय पर खरीद सकते हैं। इससे छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होता है। 1966 से पहले अम्बाला पंजाब में था ओर उस वक्त यह पोजि उन थी कि सारा जो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लुधियाना, अमृतसर और जालान्धर में ही लगाया जाता था। हरियाणा बनने के बाद तो अब हिसार और रोहतक में ही यह बातें रह गईं और अम्बाला को तो कोई पूछता ही नहीं है। इनके अलावा पानीपत में भी थोड़ी सी

इंडस्ट्रीज पनपी है मगर इस इलाके में सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

अम्बाला छावनी में सिर्फ साईंस और एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है और उसकी वजह से वह जिन्दा है। इस वक्त वहां की आबादी 1 लाख 30 हजार है। अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर करने की भारत सरकार से मंजूरी ली जाए। ऐसा करने कसे काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है। आज 15 साल पहले अम्बाला में एक इंडस्ट्रीयल एरिया बनाया गया था लेकिन वह आज तक आबाद नहीं हो सका उसका कारण यह है कि वह एरिया सड़क से काफी नीचे है, अभी तक उसके प्लॉट भी नहीं बिक सके हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई स्कीम बनाई जाए तो उस बारे में सभी बातें पहले ही देख ली जानी चाहिए कि स्कीम ठीक चलेगी या नहीं। ऐसा करने से सरकार भी नुकसान से बच सकती है और उद्योग लगाने वाले भी। 1978 में अम्बाला छावनी में फ्लड की वजह से सारा इंडस्ट्रीयल एरिया पानी में डूब गया था इसके बाद वहां पर कोई भी आदमी इंडस्ट्री लगाने की हिम्मत नहीं करता। सरकार ने इलैक्ट्रिसिटी से पहले लोगों से वायदा किया था कि अम्बाला को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड घोषित करवाया जाएगा लेकिन अभी तक वह वायदा पूरा नहीं किया गया है। मेरा कहना यह है कि सरकार अपने वायदे को जल्दी पूरा करे। वहां पर इंडस्ट्रीयल एरिया में एक ट्यूबवैल है जिसका पानी खारा है। खारा पानी होने की वजह से वह ट्यूबवैल बेकार है। इसलिए मेरी

मांग हैं कि वहा पर दूसरा ट्यूबवैल लगाया जाए।(विघ्न) अम्बाला छावनी में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां सड़के नहीं पहुंचती, वहा पर सड़क बनाने की जरूरत हैं। आज अम्बाला को इग्नोर किया जा रहा हैं। 1966 से पहले रोपड़, चण्डीगढ़ ओर नायणगढ़ के एरिया अम्बाला जिले में थें लेकिन आज अम्बाला की हालत बहुत खस्ता हैं। मै चाहता हूं कि अम्बाला जिले को भी बाकि जिलों के बराबर लाया जाए। अम्बाला के लिए एक हैवीह इंडस्ट्री लगाने की प्रोपोजल भारत सरकार को दी जाए, उससे छोटे उधोगों को काफी तरक्की मिल सकेगी और लोगो को भी रोजगार मिलेगा अम्बाला तहसील को हरियाणा में दूसरी तहसीलों के बराबर दर्जा देना कोइ हमारे साथ रियायत नहीं होगी बल्कि ऐसा करना तो इन्साफ होगा जिसकी मांग हम कर रहे हैं। ऐसा करने से अम्बाला के साथ इन्साफ होगा। यह इलाका बहुत देर से इग्नोर रहा हैं। अगरप मेरी मांग मान ली जाती हैं तो वहां पर काफी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगेंगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधान मंत्री जी के बीस सूत्री प्रोग्राम को उधोग लगाने की बात कही गई हैं। सरकार का फर्ज बनता हैं कि इस प्रोग्राम को ध्यान मे रखते हुए अम्बाला को जरूरी तौर पर इंडस्ट्रयली बैकवर्ड घोशित करवाया जाए। अम्बाला कैंट साईंस के माल की इतनी बड़ी मार्किट हैं कि दुनियां भर के देाों को वहा से माल सप्लाई किया जाता हैं। लेकिन कोई बड़ा उधोग न होने की वजह से वह तबाही की तरफ जा रहा हैं। अम्बाला में एक मैजिक आई को कारखाना हैं। वहां पर ऐसा भी तैयार किया जाता हैं कि आप भी ां के अन्दर

की तरफ से तो जो मरजी देख सकते हैं लेकिन भी े के बाहर की तरफ से कुछ नजर नहीं आता। मैं समझता हूं कि सरकार इस तहसील की तरफ ध्यान देगी और लोगों की तकलीफों को दूर करेगी। अगर इस बात का पूरे तौर पर सर्वे किया जाए तब पता चलेगा कि हमारी मांग मुनासिब है या नहीं। मैं चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करे कि अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाए।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं। किसी भी एरिए को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती हैं, खुद नहीं कर सकती है। इसलिये यह रैजोल्यूशन गलत है (गोर)

श्री अध्यक्ष: आप इस बारे में अमैडमेंट दे दें। (गोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, स्टेट गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती हैं। (गोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको रूल पढ़ कर सुनाता हूं। Rule 174 (C) at page 100 of rules of Procedures, reads as under:-

“It shall not relate to any matter whcih is not primarily the concern of the State Government.”

इस रेजोल्यूशन में यह बात होनी चाहिए थी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को रिकमेंड करे।

उधोग मंत्री(श्री लछमन सिंह): स्पीकर साहब, यह दो किस्म के होते हैं। एक तो सेंट्रली बैकवर्ड एरिया और दूसरा स्टेट बैकवर्ड एरिया। इसलिये स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती हैं।(गोर)

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, जैसे कि मेरी पार्टी के श्री हीरा नन्द आर्य जी ने प्वायंट आउट किया है, वह ठीक किया है। आपने हमारा रेजोल्यूशन इसी बिनाह पर डिस्अलाऊ कर दिया है कि इस पर सेंटरप और स्टेट के एक्ट इनवाल्ड हैं। इस मामले में भी दोनों एक्ट इनवाल्ड हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने अपने आज के रेजोल्यूशन के द्वारा किसानों की बात उठानी थी * * * * * मेरा रेजोल्यूशन बाद में लिया गया है। जबकि धमीजा साहब का रेजोल्यूशन तो किसी हालत में भी नहीं आ सकता था।(गोर)

सिंचाइ तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम गोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से लीडर आफ दि आपोजीशन से अर्ज करना चाहता हूँ कि ये हर बात को बाद में रेज करते हैं। जब कोई रेजोल्यूशन एडमिट हो जाए ओर डिस्कशन भी भुरु हो जाए तो उस समय कोई एतराज करने की कोई स्टेज नहीं होती। यह रेजोल्यूशन बैलट होकर लग चुका है और डिस्कशन भी भुरु हो चुकी है। (गोर)

श्रीमती चन्द्रावती: अगर कोई बात गलत होगी तो उसके खिलाफ किसी भी वक्त कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: पहली बात तो यह है कि मैं इस रैजोल्यूशन को एडमिट कर चुका हूँ दूसरी बात यह है कि अगर आप यह समझते हैं कि यह गलत एडमिट हुआ है तो आपको इस पर अमेंडमेंटस नहीं देनी चाहिए थीं इस रैजोल्यूशन पर आई हुई अपोजिशन की अमेंडमेंटस को भी मैंने एडमिट किया है।

Shrimati Chandravati: It does not come under the purview of the State Government to declare an area as industrially backward.

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, स्टेट भी डिक्लेयर कर सकती है। कालका, हथीन और पनारायणगढ़ के एरियाज को स्टेट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीयल बैकवर्ड डिक्लेयर किया हुआ है।

चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, हैवी इंडस्ट्रीज तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट के अडर आती हैं लेकिन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया घोषित कर सकती है।

श्रीमती चन्द्रावती: इस रैजोल्यूशन में यह कहा लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए किसी एरिया को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर करे।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, सरदार लछमन सिंह जी की यह बात ठीक है कि एक तो सैट्रली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर होता है और एक स्टेट की तरफ से बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर होता है लेकिन श्री भामोर सिंह सुरजेवाला यह बात ठीक नहीं है कि हैवी इंडस्ट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट के अडर आती है और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर कर सकती है। यदि ऐसी बात है तो इस रैजोल्यूशन में यह बात स्पष्ट करनी चाहिए थी कि ये किसी एरिया को स्टेट के प्वायंट आफ व्यू से इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर कराना चाहते हैं या सैट्रली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर कराना चाहते हैं। इसमें यह लैकुना रह गया है।

सैठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, अपोजीशन बराय अपोजीशन बात मेरी समझ में नहीं आती। जहां तक अम्बाला तहसील को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करने की बात है इस बारे में मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड करार देना बहुत ही जरूरी है। अपोजीशन वालों को मेरी बात पर इतना भार नहीं करना चाहिए। हर मੈम्बर को अपने-अपने इलाके की बात यहां सदन में कहने को हक है और ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप मेरा रैजोल्यूशन पास करके भारत सरकार को भेज दें।

अम्बाला तहसली के बारे कमे मैने जो फ़ैक्टस आपके सामने बताए हैं, क्या वे गलत हैं? अम्बाला कौन्ट से करोड़ो रूपए का माल बाहर जाता है। अगर अम्बाला में कोई हैवल इंडस्ट्री भी लगेंगी जिसकी वजह से सरकार को अरबों रूपए की फारेन एक्सचेंज मिलेगी। सही बात तो यह है कि सरकार मेरी मांग को मान ले। यदि सरकार मेरी मांग मान लेगी तो अम्बाला में छोट-छोटे उधोग लग सकेंगे जिनसे गरीब लोगो को व बेरोजगोर लोगो को रोजगार मिल सकेगा और बेरोजगारी की सम्स्या हल हो जाएगी इसके अलावा 20 नुकाती प्रोग्राम का मकसद भी हल हो जाएगा। स्पीकर साहब, जब हम 20 नुकाती प्रोग्राम का जिक्र करते हैं तो मेरे अपोजी इन के भाईयो को चिढ हो जाती है और कहने लगते है कि आप इन 20 सूत्रों मे से 5 सूत्रों के नाम ही बता दें। मै इन्हें यह बताना चाहता हू कि 20 नुकाती प्रोग्राम हमारे देा की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बनाया है और छोट उधोग धधें भी उसका एक हिस्सा है इसलिए मैं यह कहना चाहता हें कि सरकार का यह फर्ज बनता है कि 20 नुकाती प्रोग्राम को सही ढंग से सफल बनाने के लिए अम्बाला तहसील को जरूरी तौर पर इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर करार दिया जाए। इस 20 नुकाती प्रोग्राम में किसानो की भलाई के लिए,हरिजनों की भलाई के लिए और बैकवर्ड लोगों की भलाई के लिए स्पीकर साहब, जो अच्छी कात हो उसको तो कम से कम मेरे अपोजी इन के भाई अच्छा कहे। बुरी बात को तो सब बुरा कहते ही हैं। लेकिन यह अपोजि इन बराय अपोजी इन हैं।(गोर एव विघ्न)

मुख्य संसदीय सचिव(श्री अमर सिंह): स्पीकर साहब, मैं अपोजी इन के भाईयो से प्रार्थना करूंगा कि यह प्रस्ताव जेरे बहस है आप हस पर बहस होने दें। अपोजी इन वालो ने पहले ही एक घंटा खराब कर दिया हैं। मैं यह चाहूंगा कि इस तरह भाोर करने से टाईम जाया होता हैं इसलिए आप इस तरह से भाोर न करें। आप माननीय सदस्य को बोलने दें। (गोर एव विधन)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, हम तो यह चाहते हैं कि यह रैजोल्यू इन पास हों।

सैठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, अम्बाला एक डिविजन है और वहा पर कमी नर का दफतर हैं, अम्बाला में पोस्ट मासटर जनरल का भी दफतर है तथा यह एक रेलवे का बहुत बड़ा जव इन भी है। हिमाचल और पंजाब की तरफ से जितनी भी गाड़िया आती हैं, वे अम्बाला से ही होकर गुजरती है। इतना बड़ा सेंटरप होने के बावजूद भी अम्बाला को इग्नोरप किया जा रहा हैं इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना हैं कि अम्बाला तहसली को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर करवाया जाए। अम्बाला कैंट की इंडस्ट्रीज का माल बाहर के दे गों में भी जाता हैं ओरप वहां की इंडस्ट्रीज का माल बहुत अच्छी क्वालिटी का हैं। यदि वहां पर बड़े उधोग लगेंगे तो सरकार को काफी टैक्सों के रूप में भी आमदन होगी। स्पीकर साहब, अम्बाला तहसील की इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर करने से हमारे प्रान्त के लोगों की बहुत भलाई

हो सकती हैं, वहां के गरीब, मजदूर और बेरोजगार लोगों को अपने परिवारों का पालन पोषण करने के लिए रोजगार मिल सकता है। अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर करना यहां के लोगों के हित में है और प्रदेश के भी हित में है। लेकिन हम जब भी प्रान्त के हित की बात कहते हैं तभी मेरे अपाजी उन के भाई हल्ला-गुल्ला भुरू कर देते हैं। स्पीकर साहब, जिस तहसील की आबादी 4-5 लाख की हो यदि उस तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उससे प्रान्त के एक बड़े भाग का हित होगा और सरकार को भी उससे काफी आमदनी होगी। इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया जाए।

स्पीकर साहब, जो दिक्कतें अम्बाला जिले के बारे में मैंने आपको बताई हैं और जो रैजोल्यूशन हाउस में रखा गया है उसको हरियाणा सरकार पास करके भारत सरकार को रिक्मेंड कर दे। यदि ऐसा हो जाता है तो अम्बाला तहसील के लिए इस सरकार के अति अभागी होंगे। ऐसा करने से भारत सरकार भी यह सोचेगी कि हरियाणा सरकार अपने बैकवर्ड क्षेत्रों का ध्यान रखती हैं। इतना कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि अम्बाला जिले की अम्बाला तहसील को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया जायें।

I have also received two amendments to this resolution from sarvshri Mangal Sein and Bhag Mal. These will be deemed to have been read and moved together. The Hon'Members can discuss these amendments while speaking on the resolution.

Shri Mangal Sein: That in line 3 of the resolution after the words "ambala District." insert the words " Tehsil Rohtak"

Chaudhri Bhagmal: That the words "Ambala Tehsil of "appearing in lines 2 and 3 be deleted.

चौधरी भागमल (सढौरा-अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब जो प्रस्ताव हाउस के सामने आया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अम्बाला जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि अम्बाला जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करने के लिए लिखा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अम्बाला जिले की अम्बाला तहसील ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ी हुई नहीं है बल्कि सारा अम्बाला जिला इण्डस्ट्रीज के लिहाज से पिछड़ा हुआ है। अम्बाला जिले की जितनी भी तहसीलें हैं वे सभी की सभी पिछड़ी हुई हैं। अम्बाला जिले के जितने भी कस्बे हैं जैसे सढौरा, छछरोली, कालका ओर नारायणगढ़ वे सभी

के सभी हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। स्पीकर साहब, वहाँ पर कोई भी फसल नहीं हो पाती। यदि बारिश न हो तो फसल वैसे ही नहीं होती। यदि बारिश हो जाती है तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है जिस कारण सारी फसलें खराब हो जाती हैं। पानी को जहाँ तक संबंध है उसकी हालत यह है कि वहाँ पर पानी फसल के लिए तो क्या उपलब्ध होगा, आदमियों और पशुओं के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उनकी क्या स्थिति हो सकती है, यह बाप ही अन्दाजा लगाये। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, राव इन्द्रजीत सिंह, पदासीन हुए) चैयरमैन साहब, सढोरा हल्के के अन्दर छोटी-छोटी करीब 40-50 नदियाँ गुजरती हैं। वहाँ पर कई जगह पुल न होने के कारण जो लोग इन नदियों के पास रहते हैं, उससे उनको काफी नुकसान होता है और उनको कोई अतिरिक्त सहायता भी नहीं दी जाती है। वहाँ पर जो पुल बनाने की बात कही गई थी, वे पुल अभी तक भी नहीं बनाये गए हैं। कहने को तो कहा जाता है कि इस इलाके में जंगलात का काफी स्कोप है। इसके मुत्तलिक मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उन लोगों के पशुओं को पकड़ा जाता है और फाटक के अन्दर बन्द कर दिया जाता है। उस इलाके में जंगलात के माध्यम से लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है बल्कि जंगलात की पोजिशन तो यह है कि उससे वहाँ के लोगों का कचूमर निकला हुआ है। सरकार उन लोगों के हुए नुकसान को कोई मुआवजा नहीं देती। जंगलात की वजह से वहाँ के लोगों को काफी परेशानी है। यह अलग बात है कि

जंगलात के अन्दर कुछ घास या दूसरी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से वहां पर छोटी-छोटी कई प्रकार की इण्डस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं। लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा था कि हरियाणा के तमाम गावों को पक्की सड़को से जोड़ दिया गया है। इसके संबंध में मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मेरे हल्के के अन्दर भी काफी गांव ऐसे हैं। जिनकों सड़को से नहीं जोड़ा गया है और जो डारैक्टर में आते हैं। कई गावों के अन्दर पक्की सड़के बनाने के एस्टिमेट तैयार किये गये हैं। लेकिन आम कुछ नीह किया गया। वहाँ का इलाका उबड़-खाबड़ है। लोगों का आने जाने को कोई भी साधन नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस इलाके की सड़को को सबसे पहले बनाया जाना चाहिए। यदि इन गावों का सड़को से जोड़ दिया जाता है तो ये लोग अपना छोटा-मोटा कोई रोजगार इधर-उधर जा या आ कर कर सकते हैं। अगली बात मेरी यह है कि वहाँ के किसानों की हालत भी बहुत खराब है एक तो उनकी जमीन उंचाई नीचाई पर है। दूसरे वह जमीन पहाड़ियों पर है। इस इलाके के अन्दर बहुत अधिक मात्रा में पहाड़ियाँ हैं जिस कारण लोगों को काफी दिक्कत है। इन पहाड़ियों में से ही कई नदियाँ गुजरती हैं। जब बारिश हो जाती है तो इन नदियों के पास जिन लोगों की जमीनें हैं, उनकी फसल बाढ़ आने से खराब हो जाती है। इस संबंध में सरकार को मेरा सुझाव है कि बाढ़ के दिनों में इन नदियों का पानी टैक बना कर इकट्ठा कर लिया जाये और जब

जरूरत हो, उस समय किसानों को दे दिया जाये। ऐसा करने से एक तो किसानों की फसले बर्बाद होने से बच जायेगी ओर दूसरे उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यहा पर चीफ मिनिस्टर साहब और इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर सरदार लछमन सिंह जी बैठे हैं। मै दोनो से प्रार्थना करता हूं कि इन नदियों के पानी को टैंक बना कर इकट्ठा करने के लिए कोई न कोई कदम उठायें जिससेप उस इलाके के लोगों को राहत मिल सके। चैयरमैन साहब, वहां कई छोटे-छोटे कस्बे है जैसे नारायणगढ़, छछरोली, बरवाला और सढौरा आदि। इनके अन्दर म्यूनिसिपल कमेटियां तो बनी हुई हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया जाता। पैसे के आभाव के कारण वे कुछ भी काम नहीं पाती। हमारे इलाके मे जितने भी कस्बे है, उनकी तरु सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। मैरा इस बारे में सरकार को सुझाव है कि इस और वि शेष ध्यान दे और डिवैल्पमेंट के काम अधिक से अधिक करे ताकि यह इलाका भी दूसरे इलाकों के बराबर आ सके । यदि डिवैल्पमेंट के काम हो जायेगें ता लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सकेगा। वहा पर छोटी-छोटी मार्किटे हैं। अनके सुधार की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सढौरा के साथ सबसिडी देने के मामले मे भी भेदभाव किया जा रहा हैं। यदि सढौरा की तरफ ध्यान दिया जाये तो वहा पर कई इण्डस्ट्रीज लग सकती हैं। अगर नारायणगढ़, कालका, सढौरा, छछरौली और दूसरे इलाके को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोशित कर के वहां पर इण्डस्ट्रीज लगा दी जाए, तो उससे लोगों को बहुत लाभ होगा। यदि ऐसा कर दिया

जाता है तो उस इलाके को भी, जो हरियाणा के दूसरे इलाकों को सूविधा मिल रही है, मिल सकेगीं। चेयरमैन साहब, पिछले साल वहां पर कुछ छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज कुछेक लोगों ने लगाई थी। लेकिन उनको अब लोन मिल नहीं रहा यह लोन न तो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और नहीं कोई बैंक आदि उनको लोन देने को तैयार हैं जिससे वे अपनी इ इण्डस्ट्रीज का बढा सके। दूसरे इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी इन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा उल्टा यह डिपार्टमेंट भी इन को काफी परे ान करता है। गवर्नमेंट से जब लोग लोन के लिए जाते है तो इनको तंग किया जाता है। इसके अलावा उन्हे बिजली भी सबसे कम मिलती है। बिजली का न मिलना इस इलाके की प्रगति के आगे एक रोड़ा है। आजकल बरसात के कारण पानी की जरूरत नहीं लेकिन जब जरूरत होती है तो हालत यह होती है कि मुि कल से दिन मे दो घंटे बिजली मिलती है। बिलसपुर मे रोजाना 9 बजे बिजली चली जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है। रात के 9 बजे सारे को सारा इलाका अन्धेरे मे पड़ जाता है। जहां तक यहा की इण्डस्ट्रीज का सवाल है, इन इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स पर कर्ज का पैसा बढता जा रहा है लेकिन काम मिलता ही नहीं। बहुत से लोग जगाधरी से सामान लाते है लेकिन एक्सार्ज एंड टैक्से न के अधिकारी उन पर टूट पडते है। इन अधिकारियों की वजह से जगाधरी की हालत बहुत खराब है लोगों के दिलो में बडा रोश है। पिछले दिनों 18 फरवरी का वाक्या है। एक टैम्पू में चार पांच भैये जा रहे थे। इन में से एक भैये ने अपने घर जाना

था। उन भैयों पर जीप से टक्कर मार कर हमला किया गया। एक लड़के की टांग टूट गई और एक के गले की हड्डी टूट गई। एक्सीडेंट करने के बाद इतना भी नहीं कर सके कि उनको हस्पताल में दाखल करवा दें। लोगों ने उनको उठाया और होस्पिटल में दाखिल करवाया। एक भैये की टांग इतनी टूट चुकी थी कि डाक्टर ने उनकी टांग काट दिया। ये गरीब आदमी हैं, पता नहीं कौन से इलाके से रोजगार की तलाश में यहां आये थे। ये सारे के सारे मजदूर थे और इनमें से एक अपने घर आ रहा था दूसरे अपने साथी को रेल पर चढाने जा रहे थे लेकिन एक्साईज एंड टैक्सेशन के अधिकारियों ने यह समझा कि ये स्टील का सामान ले जा रहे हैं परन्तु उनके पास अपनी रिजाई वगैरह थीं खास तौर पर ई0टी0ओ0 बहुत परेशान कर रहे थे। जब इस एक्सीडेंट की एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने लगे तो पुलिस दर्ज करने से आनाकानी करने लगीं पुलिस और एक्साइज एण्ड टैक्सेशन विभाग के खिलाफ लोग जमा हो गये और दो दिन तक बंध रहा। लोग इतने एजिटेटेड थे कि दो दिन तक सारा काम बन्द रहा। पहले तो पुलिस ने प्रौपर एफ0आई0आर दर्ज नहीं की और जब की तो उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज की जो उस दिन गाड़ी नहीं चला रहा था। वह बेचारा अपने घर में सो रहा था। गाड़ी ई0टी0ओ0 या उसका इंस्पैक्टर चला रहा था। इस ड्राइवर के खिलाफ नैगलीजेंस का केस दर्ज करके चालान कर दिया। इसलिए मेरी सरकार से दुख्वास्त है कि यह एफ0आई0आर उन सेल्ज टैक्स के इन्स्पैक्टर्स के खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने

एक्चुएली इन गरीब भेयौ को मारा। इन इ0टी0औ0 औरप इन्सपैक्टरों ने यहां की इंडस्ट्रीज को बेकार कर दिया। जब इंडस्ट्रीज विभाग वाले कारखाने वालों के पास जाते हैं तो ये लोग बहिया खोल कर बैठ जाते हैं और अगर उनकी जेब में चार-पांच हजार रूपया डाल दिया जाये तो काम हो जाता है। इन अधिकारियों की धाधली के कारण यमूनानगर और जगाधरी की इंडस्ट्रीज बरबाद हो रही है। यमुना नगर और जगाधरी की इंडस्ट्रीज से स्टेट को बहुत रैवेन्यू मिलता है और अगर इसी तरह से होता रहा तो ये इंडस्ट्रीज बिल्कूल बैकवर्ड रह जाएगी क्योंकि आज सेल्ज टैक्स में बहुत लाकूने हो गये हैं जिसकी वहज से इ0टी0औ0 ने धांधली मचाई हुई है। इसलिए मेरी सरकार से दखारवास्त है कि जिन लोगों ने भईयो को बरबाद किया है, उनके खिलाफ एन्कवायरी होनी चाहिए और इन के खिलाफ दफा 307 का मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ एक्चान लिया जाए। चेयरमैन साहब, मैं हाउस को ज्यादा टाईम न लेता हुआ आपके द्वारा यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि तमाम का तमाम अम्बाला जिला हर तरह से बैकवर्ड है। लोगों को रोजगार देने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। थोड़ा बहुत साधन जमीन हो सकती है लेकिन ज्यादा साधन तो इंडस्ट्रीज से ही हो सकते हैं। लोग इंडस्ट्रीज में रूचि रखते हैं लेकिन इस रूचि का फायदा तभी हो सकता है अगर राज्य सरकार उनका प्रोत्साहन दे और सैन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई ऐड उस इलाके को दी जाए ताकि लोगों का जीवन स्तर थोड़ा बहुत ऊंचा उठ सके। सारी की सारी

पापुले उन जो देहात में बसती हैं, बिलो दी पावर्टी लाइन हैं चाहे किसान हो, चाहे हरिजन हो, बैकवर्ड क्लास का कोई आदमी हो, चाहे 20 किल्ले जमीन का मालिक हों, बड़े से बड़ा जिमीदार हो, सभी गरीब है क्योकि गवर्नमेंट की गलत नीतियों की वजह से सारी की सारी जमीन बेकार पड़ी हैं। इसी वजह से लोगों को पूरा रोजगार नहीं मिलता, तमाम का तमाम इलाका मकरूज हैं। कोओप्रेटिव सोसायटीज ने भी लोगो के नाक में दम कर रखा हैं। हमारा जो सैन्ट्रल कोओप्रेटिव बैंक अम्बाला हैं, उसने रिकवरी की होड़ लगा रखी हैं, भायद उसने ज्यादा से ज्यादा रिकवरी करके भील्ड लेनी हैं। लोगो की आर्थिक वयस्था को तहस नहस कर दिया। जिन लोगो की वोटों से सरकार बनती हैं, उन्ही लोगो का सरकार ने कचूपर निकाल दिया है। इस लिए मेरी आपसे दुख्वास्त है कि मेरी इस अमेंडमेंट को मजूर किया जाए और अम्बाला जिले के सारे एरिये को बैकवर्ड डिव्लेयर करने के लिए सिफारि की जाए।

श्री मंगल सैन (रोहतक): चेयरमैन साहब, प्रस्तावक महोदय श्री रामदास धमीजा ने कहा है कि अम्बाला दुनिया के नक्शे पर है। हरियाणा में तो इसकी नुमायां जगह हैं, यह बात ठीक हैं। वैसे तो रोहतक जिला भी बड़ा महत्व रखता हैं। चेयरमैन साहब, भौगालिक दृशिट से रोहतक जिला भी आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। केंद्रीय सरकार ने इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया करार देने की जो नीति बनाई हुई है वह ठीक नहीं हैं। सरदार

लक्षमन सिंह जी इस नीति को रिव्यू करवायें। नाहड का इलाका जिसको सैन्टरली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इन्स्ट्र लगाने के लिए नहीं जाता क्योंकि न वहां कम्यूनिके इन के साधन हैं, न रेल जाती हैं, न दूसरे साधन है। इसी वजह से वहां पर कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं जाता। (व्यवधान) सरदार लक्ष्मण सिंह जी अब कह देंगे कि जब मेरे पास यह डिपार्टमेंट था तो क्यों नहीं इंडस्ट्री लगवाई चेयरमैन साहब, हमारा समय तो एक संक्रमण काल था। * * * * *

श्री सभापति: डिफैक्ट इन वगैरा की जो बातें कह रहे हैं यह बिलकुल रिकार्ड न की जाएं।

श्री मंगल सैन: * * * * * * * * *

चेयरमैन साहब नाहड के इलाके को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड करार दिया है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। वैसे वह इलाका बैकवर्ड रहना चाहिए। इसी प्रकार झज्जर तहसील को भी इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड करार दिया हुआ है वहा पर कोई इंडस्ट्री नहीं है। रोहतक में इंडस्ट्री फलोरि ा कर सकती हैं। रोहतक की ज्योग्राफीकली सिचुए इन ऐसी हैं कि वहां इंडस्ट्री पनप सकती हैं। जिस प्रकार रोहतक की तहसील सांपला में कृषि सम्बन्धी उधोग लगे हुए हैं अगर सरकार वहां और अधि सहूलियतें दे तो और भी अधिक विकास हो सकता है। उसे भी इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया करार दिया जाना चाहिए। सन् 1967 में राव वोरेन्द्र सिंह

जी ने रोहतक को बैकवर्ड एरिया करार दिया था। उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज वहां पर लगवायी भी थी लेकिन फिर भी बहुत कम लगी हुई हैं। मेरा कहना यह है कि अगर लगावायी भी थी लेकिन फिर भी बहुत कम लगी हुई हैं। मेरा कहना यह है कि अगर रोहतक तहसील को इंडस्ट्रीज के लिहाज से बैकवर्ड एरिया को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया करार देने पर काफी सहूलियत मिल सकती हैं। लोन मिल सकता है और दूसरी फैसेलिटीज मिल सकती हैं। आजकल वहां पर इंडस्ट्रीज की बहुत बुरी हालत हो रही हैं। मेरा सरकार को सुझाव है कि यदि रोहतक तहसील को भी इस रैज्योलूशन में शामिल कर लिया जाए तो वहां के लोगों का भी भला हो सकता है। सरदार लक्षमण सिंह जी से मैं अर्ज करूंगा कि सारे प्रदेश में इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड एरियाज वैस्टिड इन्ट्रैस्टस के कारण बैकवर्ड करार दिये हुए हैं। सारे प्रदेश की इंडस्ट्री के बारे में रिव्यू कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी।

चौधरी ई वर सिंह (पुडंरी): चेयरमैन साहब, धमीजा साहब ने अम्बाला तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड करार देने के बारे में गैर-सरकारी प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है। मैं चाहूंगा कि जो अन्य बैकवर्ड एरिये है उनके बारे में भी विचार किया जाये। किसी कवि ने कहा है कि -

मेरा रोना नहीं, रोना है यह सारे गुल्सतां का।

वह गुल हूँ मै, खिजां हर गुल की है गोया खिजां मेरी ॥

केवल अम्बाला तहसील की इंडस्ट्री के लिहाज से बैकवर्ड नहीं हैं बल्कि यूरोप के मुल्कों के मुकाबले में एशिया के सारे मुल्क ही इंडस्ट्री के लिहाज से बैकवर्ड हैं। हमारे देश में भी कई सूबे हमारे अपने सूबे से काफी बैकवर्ड हैं। वहां पर इंडस्ट्री आती है, वहां पर रोजगार के साधन जल्दी आते हैं। हरियाणा प्रदेश की 80 परसेंट जनता खेती पर आधारित है। बीस परसेंट लोग इंडस्ट्री और नौकरी पर आधारित हैं। अब देखने की यह भी बात है कि हमारी इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर पर ज्यादा आधारित है। वैसे तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर अलग-अलग इम्पोर्टेन्स है। एग्रीकल्चर ही बैसिक इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर के बिना इंडस्ट्री बनप नहीं सकती और एग्रीकल्चर के बिना हमारा जीना भी सम्भव नहीं। इस देश में ज्यादातर खेती पर इंडस्ट्री आधारित है इसलिए खेती को अधिक बढ़ावा देना चाहिए। हमारे देश में खेती के सिवाए दूसरा काम धन्धा नहीं सिखाया जाता है क्योंकि खेती का काम उसे मा-बाप से विरासत में मिला है और दूसरी ओर उन्हें बढ़ने के लिए रास्ता नहीं इसलिए वे अन-एम्प्लॉयड होते हैं। गांव के लोग वही के वही रहते हैं। लेकिन हमारे सूबे में ऐसी बात नहीं है, फिर भी इस देश में बहुत से ऐसे सूबे हैं जहां पर बहुत गरीबी है। आज के दिन भूखा तो कोई भी नहीं मरता। अखबारों में कई बार आता है कि रूट्स ख कर लोग जिन्दा रहते हैं।

आजकल न्यूट्स डाईट तो बड़े बड़े सम्मानित लोगों को भी नहीं मिलती हैं इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाये धमीजा साहब ने अम्बाला तहसील की बात कही है। अम्बाला ही ऐसा एरिया नहीं है जिसे बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाये और भी ऐसे एरियाज हैं, जिनहे इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड करार देने की आवश्यकता है उन एरियाज को सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बैकवर्ड करार नहीं दिया। अम्बाला जिला पहाड़ के साथ लगता हुआ एरिया है। हिमाचल पहाड़ के साथ लगा हुआ है। यहां की जमीन भी ढलाऊ है, यहां बारिश भी ज्यादा होती है। सारा पानी बहकर चला जाता है। यहां का पानी किसी भी काम नहीं लाया जाता। अगर जमीन से पानी निकाला जाये तो वह भी बहुत गहरा है अम्बाला भाहर बड़ा मालहूर भाहर है। यहां पर छावनी भी है लेकिन वहां पर अब भी पीने के पानी के काफी किल्लत है। पानी की कमी का कारण यही है कि यहां का पानी बह कर चला जाता है। दूसरे अन्डर ग्राउन्ड पानी भी इतना अच्छा नहीं है। इस जिले में नदी और नाले भी बहुत ज्यादा मात्रा में गुजरते हैं। अम्बाला के साथ लगते हुए कुरुक्षेत्र और करनाल के इलाके बहुत जरखेन हैं। वहां के लोगों के पास साधन है लेकिन अम्बाला के लोगों के पास कोई साधन नहीं है। अम्बाला जिले की दो तहसीलों को पहले ही बैकवर्ड करार दिया हुआ है। अभी अम्बाला जिले के नगल लिफ्ट स्कीम लगी है उससे उस एरिया में कुछ फर्क पड़ेगा लेकिन फिर भी वहां पर एकड़ उतनी उपज नहीं होती है और

कै 1 अप भी इतनी नही होती। धमीजा साहब ने ठीक कहा हैं कि अम्बाला की इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत अच्छी सिचुए ान है। कई हमारे ऐसे ऐरियाज हैं, जिन्हे इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड करार दिया हुआ हैं लेकिन वहां पर इंडस्ट्रीज नही हैं। धारूहेड़ा के ऐरिया मे इंडस्ट्रीज गयी है लेकिन वह भी दिल्ली नजदीक होने के कारण गई हैं। अम्बाला मे रेलवे की बड़ी भारी सहूलियत हैं। मेन लाईन के साथ कुनैक्ट किया हुआ है। रोड के लिहाज से भी सीधा कुनैव ान हैं।

श्रीमती चन्दावती: आप तो किसान हैं। आप इस रैज्योलू ान पर अधिक न बोले। दूसरा प्रस्ताव किसानों के विशय में है। उस प्रस्ताव को भी हाउस में आने दे ताकि उस पर मैम्बर साहेबान अपने विचार रख सके।

श्री अमर सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। किसी भी रैज्यालू ान पर टाईम की लीमिट फिक्स नही की जा सकती। लीडर आफ दी अपोजि ान को बार-बार नही टोकना चाहिए।

चौधरी ई वर सिंह: अम्बाला भाहर के साथ ही अम्बाला कौन्ट भी हैं। वहां पर साईस की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हैं। अम्बाला में साईस की कोई छोटी-मोटी इंडस्ट्री नही हैं वहां पर कोई एक यूनिट नही है बल्कि बहुत से व्यक्तियों ने अपनी अलग-अलग इंडस्ट्री लगायी हुई हैं। अम्बाला में यह जो इंडस्ट्री हैं, यह सारी दुनिया में साईस का माल सप्लाई करती हैं औरप अगर अम्बाला

तहसील को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड डिवलेयर कर दिया जाये जो इसका मतलब यह है कि वहां पर कुछ सहूलियतें मिल जायेगी। उन सहूलियतों में कुछ किस्म के कन्सेंशन है जैसे कुछ जो सेंट्रल इन्कम टैक्स है उसमें भी कन्सेंशन है, बिजली का भी वहां पर ज्यादा और बेहतर प्रबन्ध किया जा सकता है, सैलज टैक्स पर भी कन्सेंशन लिया जा सकता है और उनको कर्जा भी रियायती इन्ट्रैस्ट रेट पर दिया जा सकता है। अगर वहां पर इस तरह की सहूलियतें दी जाये जो वहां की इंडस्ट्री चमक सकती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री का डिवैल्प होना कुछ इन्टनल बातों पर भी दारोमदार है कि वहां के लोग कैसे हैं। हमारे यहां पर इंडस्ट्री चलाने के लिये हरियाणा में उस तरह में मिनरल्स तो है नहीं, जिस तरह के बिहार में हैं, उड़ीसा में और बंगाल में है। वहां पर तो मिनरल्स काफी हैं और वहां पर इंडस्ट्री मिनरल्स पर आधारित हैं। जहां पर पानी से बिजली पैदा न हो सकती हो, वहां पर यदि कोयला के पिट्स के पास बिजली घर बना दिये जाये तो वहां पर बिजली सस्ती मिल सकती है बजाये उन जगहों के कि जहां पर कोयला बाहर से मंगाना पड़ता हो ओर वैगन्ज के जरिये और रेलों के जरिये वहां तक पहुंचने में भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारी स्टेट में न तो तेल है, न ही लोहा है ओरप न ही कोयला है या दूसरे कोई मिनरल्स हैं। इसलिये यहां पर तो बाहर से रा-मैटीरीयल लाना पड़ता है इसलिये यह एरिया इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड है। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हमारे बहुत से पंजाबी भाई आये और उन्होंने इंडस्ट्री को बड़ा भारी

चमकाया। यह जो फरीदाबाद की इंडस्ट्री हैं यह सब उन्ही की मेहरबानी हैं क्योंकि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उन्हे यहा पर बसाया था। फरीदाबाद में बेसिक रा-मैटेरियल भी नहीं मिलता है लेकिन फिर भी वह सारे हिन्दुस्तान के मुकाबले में बहुत आगे जा चुका हैं। इसका लाभ अकेली हमारी स्टेट को ही नहीं बल्कि सारे दे 1 को मिल रहा हैं। बहुत से ऐसे टैक्सिज हैं जो हमें इतनी ज्यादा आमदनी नहीं हैं, चाहे जमीन पर लगान की आमदनी हो या नहरी आबयाने की बात हो। वह तो हमे बराबर सी ही पड़ती हैं क्योंकि उनकी मेनटेनैस और रिकवरी वगैरा के लिये हमारा काफी खर्चा हो जाता हैं। हमारी स्टेट को जो ज्यादातर टैक्सिज मिलते हैं, वह उनसे मिलते हैं जहां से माल एक्सपोर्ट किया जाता हैं। इनके अलावा वहां का माल दूसरे सूबों में भी जाता हैं। इस तरह से जो टैक्सिज हमे आते हैं उनसे हमे हर तरह की डिवलपमेंट करनी चाहिए। किसी ने कहा हैं कि consequences of internal as well as the external nature have their effects. एक्सटर्नल नेचर को तो हमने साईंस के जरिये काबू कर लिया हैं। क्योंकि हमने उसके लाज जानकर उनको एप्लाइ किया हैं औरप इंडस्ट्रीयलाईजे 1न का काम किया हैं। इन्टरनल नेचर में लोगों का हौसला वगैरा आ जाता हैं। अगर लोगों में हौसला नहीं होगा तो वे काम नहीं कर सकेंगे। इंडस्ट्री भी तभी लगायेंगे अगर उनमें हौसला होगा। हर आदमी इंडस्ट्री लगा भी सकता। जो सबसे बड़ी चीज हैं एजुकेटिव एम्पलायमेंट की हैं। यही मसला एम0एल0ए0 का भी हर हल्के के अन्दर कम से कम एक हजार मैट्रिक पास व

ग्रैजूएट्स हर साल निकल रहे हैं। नौकरी उनमें से भायद 50 या 100 को भी हरेक कांस्टीच्यूएंसी मे नही मिल पाती होगी। यह जो पढकर निकल रहे हैं यह सारे के सारे एम0एल0ए0 के खिलाफ ही होंगे। पांच साल में इनकी संख्या 4-5 हजार हो जाएगी और यह ये कहेगें कि इनको वोट नही देनी है। वह दूसरो को तो दे देंगे लेकिन प्रैजेंट एम0 एल0ए0 को वोट नही देंगे। हालाकि इनके पल्ले तो कुछ होगा और दूसरो के पल्ले कुछ भी नही होगा। यह बड़ा जरूरी है कि हमारा जो एजुकै ान सिस्टम हैं, उसको फौरन बदला जाये। उनको इस ढंग से इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग दी जाये ताकि वे बेरोजगार न रहे उनको कोई न कोई रोजगार के साधन मुहैया हो सके और वे कोई काम सीख सकें। आज क्या हालत हैं। आज लडका अगर 10 वी पास कर लेता हैं तो वह खेती की काम नही करता क्योंकि हमने उसको नर्म बना दिया हैं। फिरप हम उससे उम्मीद करते हैं कि वह खेती का काम कर दे। खेती का काम वह कैसे कर देगा। वह ट्रैक्टर पर बैठकर या म िन की सहायता से तो खेती का काम कर देगा लेकिन अदरवाईज काम नही कर सकता। उसका हमने रहन-सहन इस ढंग का बना लिया हैं कि वह आराप्रस्त हो गया हैं। हमने खुद की उसको नर्म बना दिया हैं। Man is a undle of habits and habits are acquired. पहले हम उसको सख्त बनायें , फिर वह खेत मे काम कर सकता हैं। एक बार की बात मैं आपको सुनाता हूं तजुर्बा करने काक अकबर बाद ाह को बड़ा भोक था। एक दिन अकबर कही जा रहा था। उसने क्या देखा कि एक जमींदार डले पर सिर रखे हुए सो रहा

था। जब सोया होगा वहा पर छाया थी और अब धूप आ गयी थी लेकिन वह वही पर सो रहा था।

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। चेयरमैन साहब, चौधरी ई वर सिंह जी बड़े पुराने लैजिस्लेटर हैं। मै जानती हूं कि इनका हक तो था मिनिस्टर बनने का लेकिन इनको बनाया नहीं गया। वे बे तक कितना ही बोल ले भजन लाल जी इनको मिनिस्टर बनाने से ता रहे लेकिन अगर ज्यादा बोलने से मिनिस्टरप बनते हों फिर तो ठीक है वरना क्यो हाउस का टाईम जाया कर रहे हैं।

चौधरी ई वर सिंह: उन्होंने बीरबल से कहा कि यह कैसा आदमी हैं जो धूप में भी सो रहा हैं। ओर सिर के निचे डले का सिरहाना बनाया हुआ हैं। बीरबल ने कहा कि बाद गह सलामत, जिस तरह का मनुश्य नर्म या सख्त होता हैं, उसको उसी हालज में नींद आ ही जाती हैं। बाद गह ने कहा कि क्या यह नर्म भी हो सकता हैं। बीरबल ने कहा क्यो नही। 6 महीने के अन्दर – अन्दर आपको इसे नर्म करके दिखा सकता हूं। बाद गह ने कहा, बहुत अच्छा करके दिखाओं। बीरबल उस आदमी को फतेहपुर सिकरी ले गया। उसके रहने के लिए अलग से कोठी दे दी गयी और सारा ऐ गो-आराम का सामान मुहेया करवा दिया जायेगा। हर रोज उस जमींदार से उसका हाल पूछा जाता। उसकी देखभाल के लिये ओर मैडीकल एग्जामिने उन के लिए बाकायदा एक डाक्टर नियुक्त कर दिया गया। उससे उसकी सेहत के बारे में

बाकायदा रिपोर्ट ली जाती थीं जब 4-5 महीने गुजर गए तो बीरबल ने एक दिन पेजे को यह कहा कि आज इसके बिछाने में दो-तीन बिलोले एक तरफ और दो-तीन बिनोले दूसरी तरफ डाल देना। सुबह जब जमींदार सभा में आया और बाद ग्राह सलामत ने पूछा कि कहो क्या हाल हैं। जमींदार बोला आज रात को नींद ही नहीं आयी। लठ्ठ से सारी रात कड़कते रहे। कभी इधर करवट लेता था ओर कभी उधर, लेकिन नींद ही नहीं आयी। बीरबल ने कहा जनाब, यह वही जमींदार है जो एक दिन डले का सिरताना बनाकर जमीन पर सो जाता था लेकिन अब इतना नर्म हो गया है कि दो-चार बिनोले भी इसका चुभने लगे हैं। यह तो नर्म हो गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह तो सारा ट्रेनिंग पर डिपैन्ड करता है। हमारे नौजवान इतने नर्म हो गये हैं कि वे कोई सख्त काम करना पसन्द ही नहीं करते और न ही वे कर सकते हैं। हमें उनको इस किस्म की ट्रेनिंग देनी चाहिए जिनसे वे सख्त काम कर सकें। यह बात अलग है कि कुछ बैसिंज चीजे है जो उनको हमें सिखानी ही पड़ेगी क्योंकि आम नोलेज के लिये वे जरूरी हैं। मेरा कहना यह है कि हमारी शिक्षा में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी शामिल होनी चाहिये।

श्री हरि चन्द हुडा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, चेयरमैन साहब। अभी मेरे दोस्त ने एक बात कही जो इंडस्ट्री के बारे में थी। इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसे हरेक आपसी नहीं समझ सकता। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि गांव में जो जूता चमार

बनाता है, धानक जो कपड़ा बनाता है और किसान जो हल चलाता है, क्या उसको इंडस्ट्री में नहीं गिना जाता। अगर वे उनका इंडस्ट्री मानते हैं तो यह जो गाव की 50-60 फीसदी आबादी वहां की इंडस्ट्री को चलाती है, उसको आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या किया है। मैं यह कहता हूँ कि गाव की इंडस्ट्री उजाड़ कर भाहरों को इंडस्ट्री के मामले में क्यों बसाया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि यह कहेंगे कि यह तो टैक्नीकल धन्धा है इस धन्धे को कोई नहीं जानता। इस सरकार ने धानक की जो कपड़े की गांव में इंडस्ट्री है और चमान की जो जूते बनाने की इंडस्ट्री है, उसके लिये कुछ नहीं किया है। क्या यह उसको इंडस्ट्री नहीं मानते।

चौधरी ई वर सिंह: चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि अगर नौजवानों की सही तालीम का मसला हल करना है, तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि यह बड़ा गम्भीर मसला है और उनको इस मसले को जानने का टाइम भी निकालना चाहिए। एजूकेटन सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है। हमें सिर्फ वक्त ही नहीं काटना है बल्कि नौजवानों की एनर्जी का सही इस्तेमाल करना है। अगर एक नदी में बाढ़ आती है तो आप तूफान को रोक नहीं सकते। आप उसकी डायरेक्टन तो चेंज कर सकते हैं लेकिन तूफान को रोक नहीं सकते। नौजवानों की एनर्जी को हम ठीक ढंग से ढाल सकते हैं बस तब कि एजूकेटन सिस्टम में कुछ

तबदीली कर दी जाए। खेती कोई रबड़ तो है नहीं कि अस्सी फीसदी आबादी जमीन पर गुजारा कर सके। आबादी तो बढ़ती जा रही है। जमीन कम होती जा रही है। आबादी ज्यो-ज्यों बढ़ती जा रही है इंडस्ट्री लगती जा रही है, सड़के बनती आ रही हैं, ओर जंगला को भी बढ़ाने का सरकार का प्लान है। क्योंकि वर्षा बढ़ानी है, पानी का बहाव ठीक करना है ज्यो-ज्यो जमीन कम होती जा रही है गावों में रहने वाले लोग भी सोचने लगे हैं। पहले तो लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में विचार करते नहीं थे बच्चे ज्यादा होते थे तो जमीन भी बंट जाती थी।

श्री वीरेन्द्र सिंह : चैयरमेन साहब, यह जो रैजोल्यूशन है यह तो अम्बाला को इंडस्ट्रीयली बैकवर्ड करने के बारे में है, इसमें फैमिली प्लानिंग कहा से आ गई। मेरी सबमिशन है कि टाइम लिमिट कोई बांध दीजिए क्योंकि इसके बाद एक बहुत जरूरी रैजोल्यूशन है। इसलिए चैयरमेन साहब, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समय की सीमा बाधिए।

श्री सभापति: आप बैठिये यह भी काफी इम्पोर्टेंट मसला है। आपको भी पूरा टाइम दिया जाएगा।

चौधरी ई वर सिंह: चैयरमैन साहब, बढ़ती हुई आबादी का एक ही इलाज है कि अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगाई जाए। पैदावार की फिगर हमें बता रही है कि हमारी उपज बढ़ी है लेकिन क्योंकि आबादी भी बढ़ गई इससे उस उपज का ज्यादा

लाभ नहीं हुआ। सरकार ने बिजली की उपलब्धि लगाए हैं अन्डरग्राउंड पानी को टेप किया गया है और इन सब बातों से हमारी पैदावार बढ़ी है। लेकिन जमीन की पैदावार बढ़ने से भी हम सारी आबादी को पूरा काम नहीं दे सकें हैं। चैयरमैन साहब, देहात में जो हमारे लोग है वे केवल अनएम्पलायड ही नहीं अन्डर एम्पलायड भी हैं और इसलिए उनका जीवन का स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लि जरूरी है कि इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं। आज हम यह देख रहे हैं कि खेती करने वालों को उतना नहीं बचता जितना बचना चाहिए। एग्रीकल्चर के आधार पर जो प्रोसेसिंग प्लांट लगात हैं वे कहीं ज्यादा नफा कमा सकते हैं। जमीन की तो लिमिट हैं कभी भी वह सरप्लस डिक्लेयर हो सकती हैं लेकिन इंडस्ट्री के साथ ऐसा नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : चैयरमैन साहब, हम एम0एल0ए0 हैं। हम स्टूडेंट्स नहीं हैं। यह तो हमको पढा रहे है जैसे हम विधार्थी हों।(गोर एव व्यवधान)

चौधरी ई वर सिंह: चैयरमैन साहब, मे कह रहा था कि हमारी जरूरत हैं उसका इलाज केवल इंडस्ट्री ही हैं। चैयरमैन साहब, भाहर का जो नौजवान है वह तो नौकरी कम मांगता हैं क्योंकि भाहर में व्यापार को माहौल हैं। नौकरी तो देहात का जो नौजवान हैं, वह मांगता हैं क्योंकि वह रिस्क से डरता हैं। उसको हम समझाते भी है कि बैंक से उसको कर्जा मिल सकता हैं बैंक

से कर्जा लेकर इंडस्ट्री लगाओं, लेकिन वह घबराता हैं कि अगर नुकसान हो गया तो वह क्या करेगा। उसको डर लगता हैं कि कहीं अगर नुकसान हो गया तो घर में जो थोड़ी बहुत पुंजी है वह भी खत्म हो जाएगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, इनको कितना टाईम बोलने के लिए दिया गया हैं। कृपया इनका टाईम फिक्स करिए।

श्री सभापति: यह बहुत इम्पोर्टेंट मैटर हैं। जब आप बोलेंगे तो जितना टाईम आप चाहेगं, उतना मिल जाएगा।

चौधरी ई वर सिंह: चैयरमैन साहब, देहात कि लड़के बाहर चले जाए तो बाहर जाकर वे छोटे से छोटा काम कर लेंगे लेकिन घर पर रहकर वे कोई काम नहीं करते। यह साइकलोजिकल हैं।

श्री बसन्ती देवी: चेयरमैन साहब, यह कहावत हैं कि आदमी जो किसी टॉपिक पर घंटो बोल सकता हैं लेकिन औरतें तो बगैर टॉपिक के ही घंटो बोल सकती हैं। इन्होंने तो हद कर दी हैं।(हंसी)

चौधरी ई वर सिंह: चैयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो अन्डर एम्पलायड युथ हैं उनके लिए कोई इस किस्म का प्रबन्ध हो(व्यवधान व भाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह : चेयरमेन साहब, आप कोई टाईम लिमिट मुकरर करे तो अच्छा रहेगा।

चौधरी ई वर सिंह: चैयरमैन साहब, मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना हैं कि जो लड़के इंडस्ट्री लगाना चाहे उन्हे पहले छः महीने की ट्रेनिंग दी जाए। जैसे वनबिन्डों सिस्टम बनाया हुआ हैं, उसमे उनको छः महीने की ट्रेनिंग भी दी जाए।

चौधरी रोान लाल आर्य: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हे कि यह धीमी गति के समाचारों को जरा तेज रफतार कर दीजिएगा ताकि सुना जा सके। (गोर)

श्री सभापति: ई वर सिंह जी, आप वाईड—अप कीजिएगा।

चौधरी ई वर सिंह: चैयरमैन साहब, लड़कों को कम से कम कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिये 6 महीने या साल की ट्रेनिंग दी जाए जिसमे यह बताया जाए कि यहां से कर्जा मिलता हैं, यहां से कर्जे के फार्म मिलते हैं, फार्म इस तरह से भरे जाते हैं आदि—2 (गोर एव व्यवधान)

चौधरी धीरपाल सिंह: चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यहां पर आनरेबल मैम्बर ने यह कहा हैं कि गांव के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे इन्डस्ट्रीज की तरफ खास ध्यान नहीं देते और उधोग लगाने में हिचकचाते है लेकिन मे यह कहना चाहता हूं कि मेरी कास्टीच्यूएंसी बादली के दो गांव

इस्माइलपुर ओर मुंडाखेड़ा हैं, वहां पर लोगों को भैंस-गाए खरीदने के लिए भी डी0आर0डी0ए0 से लोन नहीं मिलता तो सरकार उन लोगों को इन्डस्ट्रीज लगाने के लिये क्या लोन देगी। अगर सरकार बच्चों को उत्साह बढ़ाना चाहती है तो उनको इन्डस्ट्रीज के लिये लोन दे ताकि वे वह पर इन्डस्ट्रीज लगा सकें लेकिन यह कहना गलत है कि गांव के नौजवान इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते।

श्री सभापति: चौधरी साहब, अब आप वार्ड-अप कीजिएगा।

13.00 बजे

चौधरी ई वर सिंह: मैं कह रहा था कि नौजवानों को पहले 6 महीने की या साल की इन्डस्ट्रीज लगाने के लिए ट्रेनिंग देनी चाहिए और साथ ही उन्हें बताना चाहिये कि लोन के लिये यह यह फार्मज है और यहां से फार्मज मिलते हैं। इस तरह से फार्मज भरे जाते हैं। बैंक भी लोन देने के लिए तैयार है। इस प्रकार की जानकारी पहले नौजवान बच्चों को दी जानी चाहिए जैसे पैडी एरिया है, वहु पर गते को काम बहुत होता है, उन्हें पहले वहा पर ले जाकर गते की इन्डस्ट्रीज दिखाई जाए। उसके बाद तभी वे अपना काम कर सकते हैं। टैक्नीकल ने हाऊ पूरे ढंग से दिया जाए। क्या वजह है कि हिसार के रहने वाले और लोहे का काम करने वाले ही लोहे के कारखाने लगातार रहे और दूसरे

लोग इस से वंचित रहे। इस की वजह यह है कि जो टैक्नीकल नो हाऊ है वह उनके खून के अन्दर दाखिल हो चुका है। उन्हे इस चीज को तजुरबा है। इस प्रकार पहले ही अगर नौजवानो को ट्रेनिंग देकर यह बता दिया जाए और उनको यह पता लग जाए कि वह भी इन्डस्ट्रीज लगा सकते हैं तो हरियाणा प्रान्त काफी आगे बढ़ सकता है। इस के लिये टैक्नीकल आदमियों की मदद भी ली जानी चाहिये। जैसे जीरी का छिलका होता है इस बारे मे, मैं आपको बताता हूं कि यह पहले बिल्कूल फिजूल मे जाता था और लोग खुद कहते थे कि यह ले जाओ। अगर कोई पट्टे उसमे चला जाता था तो वह झुलस करप ही मर कर ही बाहर निकलता था, नीचे ही नीचे चला जाता था, कितना नुकसान होता था, क्योकि इस बारे में हमे ज्ञान नही था कि इसका प्रयोग कहां किया जाए। इसक के कारण पोलूशन की भी बड़ी प्रोबलम थी। सड़को पर आने जाने की भी दिक्कत होती थी। लेकिन अब इस बारे मे पता चला है और इस साल भौलज्र का 50-50 हजार और 1-1 लाख का भूसा बिका है। क्योकि अब लोगो को टैक्नीकल नो हाऊ का पता लग गया है। आत इससे कई चीजे बनती है इसका जलाया जा सकता है सीमिन्ट भी बनता है और दूसरे कई कामों के लिये इस्तेमाल भी होता है।(घण्टी) चेयरमैन साहब, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे टैक्लीकल आदमी, अफसरप और सम्बन्धित मिनिस्टर बाहर के मुल्को में जाए और वहो से जानकारी हासिल करके उसे अपने यहां पर लागू करें। जैसे कि जापान है, जापान के अन्दर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज बहुत ज्यादा है जिसके

कारण उसका नाम सारे वि व में प्रसिद्ध है, एग्रीकलचर तो वहां पर केगल 7-8 परसेन्ट सबसीडाइज्ड हैं मैन उनका उत्पादन तो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज से होता है । ऐसे मुल्क को भी ऊंचा उठा सकते हैं । किसान की खेती का अगर हिसाब लगाया जाए तो आपको पता चलेगा कि हमारा किसान कहां पर स्टेण्ड करता है । किसान के बारे में पंजाब के महार कवि इकबाल जी ने यह कहा है—

क्या तेरी जिन्दगी का है राज, हजारों वर्ष से है ते
खाके बाद,

इसी खाक में बुझ गई तेरी आग, सुबह की अता हो
गयी अब ता जाग,

जमीन में है खामियों की बारात, नहीं इस अन्धेरे आबे
हतात ।

मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे एक्सपर्ट्स, आफिसरप, टैकनीकल आदमी और सम्बन्धित मिनिस्टर बाहरप जाकरप इस टैकनीक को न समझेगो तब तक हमारे हरियाणा में इन्डस्ट्रीज का पनपना दूभर हो जाएगा । इसलिये सम्बन्धित मिनिस्टरप अफसर वगैरह बाहर जापान जैसे इन्डस्ट्रीयल दे गों मे जाए और वहा से आकर फिरप अपने किसानो को ओरप नवयुवकों इस बारे मे ज्ञान दे कि इस तरह सू इन्डस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं । यह रा-मैटैरियल हैं, जिसके

अनुसार आप यह यह इन्डस्ट्रीज लगा सकते हैं। सब कुछ बतलाएं। हमारे पास यहां पर मिन्डरलज की कोई कमी नहीं है। इंतजाम करे कि अम्बाला के साथ-साथ सारे हरियाणा सूबे का इस बारे में सर्वे करवाया जाए कि कहां-कहां कौनप सी इन्डस्ट्रीज पनप सकती है किस-किस इन्डस्ट्रीज का कहां-कहां क्या स्कोप है। एग्रीकलचर की तरफ हम कितना ही बढे लेकिन जब तक हम इन्डस्ट्रीज की तरफ खास तबज्जो नहीं देगे, तब तक लोगों का प्रान्त का और नवयूवकों का स्टैण्डर्ड ऊंचा नहीं उठ सकेगा। इन भाब्दों के साथ चेयर मैन साहब, मैं आपका धन्यावाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

Shri Nihal Singh: Mr. Chairman Sir, enough discussion has taken place on this issue and now i move that the question be pat.

Mr. Cahirman: Some More members still want to speak on as this resolution. Therefore, the discussion will continue.

13.00 बजे

ठाकुर बहादूरप सिंह(दरबां कलां): चेयरमैन साहब, मैं धमीजा साहब द्वारा प्रस्तुत किये गये रेजोन्स्यू इन जोकि अम्बाला तहसील को इन्डस्ट्रीयल बैकवर्ड डिक्लेयर करवाने के लिये, रखा गया है। उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यहां पर

मेरे साथियो ने बोलते हुए काफी सारी बातें हाउस के सामने रखी हैं और यह भी बताया है कि हमारी हरियाणा की जमीन और ज्यादा वजन सहन नहीं कर सकती। यहां तक खेती की पैदावार का समबन्ध है, वह पैदावार इन्डस्ट्रीयल पैदावार से बहुत ही कम है। भायद आप सब लोग मेरे से सहमत होंगे कि किसान को अपनी जिन्स बेचने के बाद बैंक इंस्ट्रैस्ट रेट से भी वसूली होती है। अनाज को हम किसान लोग बाहर तो भेजते हैं लेकिन उसकी रिटर्न हमें होती है, वह बहुत की कम होती है। वह बैंक इंस्ट्रैस्ट रेट से भी कम बैठती है। यहां पर कई सदस्यो ने यह परपोजल भी रखी कि केवल अकेले अम्बाला कौन्ट को ही कया हरियाणा के दूसरे इलाकों को भी इन्डस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाए और दूसरे इलाके भी इस में शामिल किये जाए। बहुत से भाईयो ने अपने अपने इलाके की बातें ही कही है लेकिन यह सोच कितनी अच्छी है कि सारे हरियाणा के बारे ही सोचा जाए। एक वह काम जिसमें कि मुनाफा ज्यादा है वह किसी एक को मिले और दूसरे उससे महरूम रहें, इसके लिये अगर लोग अपने अपने इलाकों की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से यह उचित नहीं। हमें सब को मिलकर अपने सभी भाईयो की आम लोगों की भलाई के लिये और सारे हरियाणा की भलाई के लिये ही सोचना चाहिये। जिन लोगों को हम यहां पर रिप्रजैन्ट करते हैं, हमें उनक की भलाई के लिये सोचना चाहिये और सरकार को कहना चाहिये ताकि वे लोग समझे कि हमारे इलाके के लिये हमारी नुमाइन्दे यह यह कर रहे हैं। अब मैं अपने जिले सिरसका की ही बात करूंगा जोकि आज

पंजाब के बार्डर पर हैं सिरसा जिले में चावल, कपास और आयल सीडज बहुत पैदा हाते हैं। खेती के लिहाज से सिरसा जिला ने हरियाणा में अच्छा नम्बर बनाया हुआ हैं लेकिन इसके साथ साथ सिरसा जिला इन्डस्ट्री के मामले में बिल्कूल न के बराबर है। वहा पर होई इन्डस्ट्रीज नही हैं। आज खेती से लोगों को बहुत ज्यादा पेसा नही मिलता और न ही इससे पूरा रोजगार मिलता हैं। इसका कारण यह है कि आज जमीन से पैदावार लेने के लिये खर्च बहुत करना पड़ता हैं। लैंड सीलिंग की वजह से लोगों के पास जमीन घटती गई और उनकी आमदनी भी घटती चली गई। उस एरिया में लोग चाहते है कि इन्डस्ट्री लगे। लोग इस तला 1 मे है कि उनका जो पैसा घटता ही चला जा रहा हैं वह पैसा इन्डस्ट्रीज के रूप में प्रोडक्टिव बनाया जाए। आज पोजी 1न यह है कि सिरसा जिला के लाग या तो हरियाणा से बाहर जाकर इन्डस्ट्रीज लगा रहे हैं या हरियाणा मे ही उस जगह लगा रहे हैं जो इलाका सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से इन्डस्ट्रीयली बैकवर्ड डिक्लेयर किया हुआ हैं। मैं अपने सब साथियों का समर्थन चाहूंगा कि सिरसा जिले को भी बैकवर्ड घोशित किया जाएं हम जब पंजाब साईड से सिरसा मे दाखिल होते हैं तो हरियाणा की तरफ की सड़क पर चढते ही आपको पता चलता हैं कि हम हरियाणा में आ गये हैं। दूसरे सूबों के लिहाज से हरियाणा की सड़के बहुत ही अच्छी हैं। हम जब से हरियाणा में दाखिल होते हैं तो हर जगह ऐसा दिखाई देता हैं कि जैसे हर जगह पर दिवाली मनाई जा रही हो। इसका कारण यह है कि हरियाणा में हर गांव में घर घर और खेत खेत

में बिजली के बल्ब जल रहे हैं। सिरसा जिले ने हर लिहात से आगे बढ़ने की कोशिश की है लेकिन भटिठा, मुक्तसर वगैरह की साइड से जब लोग आते हैं तो वे कहते हैं और ठीक हैं लेकिन इन्डस्ट्री के नाते सिरसा न के बराबर ही है। सिरसा जिले में नहरे भी हैं और ट्यूबवैल भी हैं। जो तक नहरो का ताल्लूक हैं, सिरसा टेल पर हैं। वहां पर खाल पकके बनाए गए हैं और जमीन के एक-एक एकड़ में खाल बने हुए हैं मगर पानी टेल तक नहीं पहुंचता। जिसका खेत आखिर में है वही यही समझता है कि उसको खाल का कोई फायदा नहीं औरप उसे केवल टैक्स ही लगा है। (विधन) इसी तरह से उस इलाके में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो महेन्द्रगढ जिले की तरह रेतीले एरियात हैं। वहां पर इरीगेशन के पूरे साधन नहीं और कहत पड़ता है। अभी मंत्री जी ने हेल स्टार्म और कहत की वजह से वहा पर बुआइ नहीं हो सकती। अधिकारियों से जब मांग की गयी कि ऐसे इलाकों में भी मुआवजा दिया जाए तो उनहोने बताया कि जिस जमीन में का त की गई को ओर वहां कहत पड़ गया हो, वहां पर सहायता दी जाती है। वहां पर बारिश न होने की वजह से, इरीगेशन साधन न होने की वजह से जमीन का त नहीं हुइ ओर उसको कोई कम्पनसेशन नहीं दिया जाता, यह ठीक बात नहीं है। किसान इतना वजन नहीं उठा सकते आज हमारपे सिरसा जिले में स्कूल, कालेज और आई.टी.आई. वगैरह हैं। लेकिन वहां से बच्चे पढ कर और टैनिंग लेकर कहां जाकर नौकरी तलाश करें। अगर इस एरिया में इन्डस्ट्री डिवलैप कर दी जाए तो उस एरिया की

बेरोजगारी को दूर करने का यह ही एक साधन होगा। मैं तो इस राय को हूँ कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ही इन्डस्ट्री डिवैल्प न ही जाए बल्कि 10-10 गावों के बीच में दो दो, चार-चार यूनिट लगा दिये जाए ताकि बेरोजगार लोगों को सुविधा मिल सके। अगर ऐसा कर दिया जाता है। तो कोई आदमी यह कह कर भूखा नहीं सोयेगा कि आज मुझे काम करने की जगह नहीं मिली। सिंरसा जिले के आदमी बहुत मेहनतक ा हैं। आपने 1947 से पहले सुना होगा कि वहा की जमीन इतनी सीधी नहीं थी। जैसी आज नजर आती हैं। वहा के मेहनतक ा किसानों ने खेतों को सीधा किया और प हर लिहाज से पैदावार बढ़ाई लेकिन खेती से ज्यादा आज इन्डस्ट्री महत्वपूर्ण हो गई है। इन्डस्ट्री में रिटर्न देखी जाती हैं और जहां रिटर्न का सवाल है खेती इन्डस्ट्री के मुकाबले बहुत पीछे रह गई है। हमारी सरकार चाहती है कि हर आदमी खु ाहाल होए उसकी इन्कम बढे और कोई बेरोजगान न हो। आज हमारे चाहे ए.आर.डी. की स्कीम है, बीस सूत्री प्रोग्राम के तहत हर गांव मे तरह तरह के साधन पहुचे हैं। हरियाणा में कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां जरूरत मन्द को जिसके पास पैसा नहीं था, काम करने की ताकत थी, हिम्मत थी, मेहनत कर सकता था लेकिन पैसे का साधन न होने की वजह से वह अपना काम नहीं कर पाय, सहायता नहीं दी गई होगी। चाहे ऊंटगाड़ी वाला हो, चाहे भैंस रखने वाला हो, चाहे भेड-बकरी रखने वाला हो और चाहे कोई और चाहे कोई दूसरा छोटा मोटा काम करने वाला हो, जब तक उनको पैसों की सहायता ही मिलेगी तब तक उनका

काम रूका रहेगा। बगैर पैसे की सहायता से उसके सारे काम रूके रहेगे उनका कोई भी काम पूरा नहीं होगा। चेयरमैन साहब, हम विधायकों के द्वारा सरकार से अपनी मांगें मांगने की वजह से भायद ये सारी स्कीमे मंजूर हुई हैं और हर गाव में उनका फायदा लोगों को पहुंचा है। चेयरमैन साहब, वे गरीब लोग जो बेचारे अपने जिस्म को ढकने के लिए पूरा कपड़ा नहीं पहन पाते थे वे लोग इन स्कीमो से फायदा उठा कर अपना रोजगार चला रहे है और अपने परिवार को पालन पोशण कर रहे हैं। इसी तरह से जितनी भी दूसरी स्कीमें है उनसे हर जगह पर फायदा हो रहा है लेकिन सबसे ज्यादा फायदा अगर हो सकता है तो वह इन्डस्ट्री से हो सकता है। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सिरसा मे मेहनती लोगों को इन्डस्ट्री कर फ़ैसीलिटीज दे दी जाए और उस एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन्डस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया घोशित करवा दिया जाए तो मैं हाउस को यकिन दिलाता हूं कि सिरससा भी फरीदाबाद में इन्डस्ट्रीयल एरिया से कम नहीं रहेगा। चेयरमैन साहब, अगर सारे हरियाणा प्रान्त को इन्डस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया घोशित कर दिया जाए तो इस प्रान्त के मेहनती लोग और दिमागी लोग अपने प्रान्त हरियाणा को स्वीटजरपलैंड बना कर दिखा सकते है और जो दूसरे प्रदे । पहले से बहुत आगे जा चुके हैं उनके इस प्रान्त को और अपने दे । को ला सकते हैं। इसलिए चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहता हू कि सिरसा जिले के लोग अपनी मेहनत से बहुत सी चीजें पैदा करके अपने प्रान्त

के दूसरें भाईयो की और दे । के दूसरे भाईयो की सेवा करते हैं । अगर सिरसा जिले को इन्डस्ट्रीयली बैकवर्ड एरिया घोशित कर दिया जाए तो वहां के लोग दे । की और प्रान्त की काफी सेवा कर सकेंगे । इसके अलावा चेयरमैन साहब, हमारे प्रान्त में बिजली के बहुत से बड़े-बड़े प्लांट बनाए जा रहे हैं । (तोर) चेयरमैन साहब, जब भी हम बोलने के लिए खड़े हाते हैं तो मेरे विरोधी पक्ष के भाई हल्ला गुल्ला करना भुरू कर देते हैं । क्या इन का यही काम रह गया है । कि इनका नाम अखबारों में आ जाए कि फलां-फलां अपोजि । न के एम.एल.ए. ने इस तरह की बात कही । मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि हमे जिन लोगों ने यहां पर चुनकर भेजा है हमे उनकी भलाई के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ओर उनको फायदा पहुंचाने के लिए कोई काम करना चाहिए । चेयरमैन साहब, मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों को याद होगा कि जग हम लोग अपने वोटरो से वोट मांगने गए थ, उस समय हमने उन से यह कहा गि कि ए भाईयों अगर आम मुझे एक बार विधायम बनने का मौका देंगे ता हम आप के हकों और इन्साफ को आपके घर तक पहुंचायेंगे । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, हम सब ने लोगों के हकों की ओर इन्साफ की बात करते है तो मेरे विरोधी पक्ष के भाई परे तान हो कर हल्ला-गुल्ला करने लग जाते हैं । अध्यक्ष महोद, हमारे प्रान्त में और खास करके सिरसा जिले मे इन्डस्ट्रीज को डिवैल्प करना बहुत जरूरी है । हम ने लोगो से वायदा किया हुआ है हम आप

लोगो को खुाहाल बनाएगें लेकिन हमारा प्रान्त खुाहाल तभी होगा जब यहां पर इन्डस्ट्रीज डिवैल्प हो जाएगी।(गोर एवं विध्न)

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डरप हैं। पिछले साल हमने सी.एम. साहब हो पोलिटी गियन आफ दि ईयर डिकलेयर किया था। और इस बार ठाकुर बहादूर सिंह को स्पीकर आफ दि सै गन डिकलेयर कर देना चाहिए। (गोर एवं विध्न)

ठाकुर बहादूर सिंह: स्पीकर साहब, बिजली के प्रोजैक्टस का जहां तक ताल्लूक हैं, मै इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे पी.यू.सी. का मैम्बर होने के नाते बिजली के प्रोजैक्टो को देखने का मौका मिला हैं लेकिन यदि मेर विरोधी पक्ष के भाई यहां हाउस मे बैठ कर उन प्रोजक्टो के बारे मै कुछ कहे तो कोई बात नही बनती। इन्हे वे प्रोजैक्ट मौके पर जा कर देखने चाहिए। स्पीकर साहब, जैसे ताजेवाला बैराज की बात हैं उस पर हमारे इंजीनियर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, हमारी स्टेट का बहुत सा पैसा उस पर लग रहा हैं और उससे प्रान्त को कितना बैनीफिट होगा, इन बातों का पता वहां जा कर देखने से लगता हैं। इस के अलावा पानीपत का थर्मल प्लांट कुछ साथियों ने देखा होगा और कुछ साथियों ने नही भी देखा होगा। जिन साथियों ने नही देखा वे भी उस प्लांट के बारे में टीका-टिप्पणी करनी भुरू कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने सरकार का विरोध करना होता हैं। * * * * * (गोर एवं विध्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि ठाकूर बहादूर सिंह जी मैम्बर्ज के प्रति कह रहे हैं * * * * * यह मैम्बर्ज पर एसपर्सन कास्ट कर रहे हैं यह आबजै गनेब्ल बात है। यह रिकार्ड पर नहीं आनी चाहिए। (गोर)

ठाकुर बहादूर सिंह: स्पीकर साहब, मैं आप के द्वारा मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा और भायद विरोधी पक्ष के भाईयो के दिमाग में भी यह बात होगी कि सिरसा जिले के मुख्यमंत्री रह चुके हैं इसलिए सिरसा जिले ने बहुत तरक्की कर ली होगी, बहुत बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज वहां लग गई होगी, वहा के किसान बहुत खु गहाल हो गए होंगे और सिरसा जिले में विकास के बहुत काम हुए होंगे। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप यह समझ कर सिरसा जिले को इग्नोर न करें कि वहा का नुमायन्दा मुख्यमंत्री रह चुका हैं। इसलिए पहले ही वहां पर बहुत कुछ हो गया होगा। जब चौधरी देवी लाल मुख्यमंत्री थे तो वे चाहते थे कि सिरसा जिला तरक्की करे लेकिन मैं यह समझता हूं कि सिरसा जिले ने कोई तरक्की नहीं की। उस समय उनके साथियों ने उनका कोआप्रेट नहीं किया। उनके समय में सिरसा में एक बिजली घर बनना था लेकिन उनके साथियों ने और उस समय बिजली मंत्री ने उनका साथ नहीं दिया। पता नहीं वे उन का साथ कयो नहीं देना चाहते थे। वह बिजली घर भी नहीं बन सका। उस जिले का प्रतिनिधी मुख्यमंत्री रह चुका हैं। उसके बावजूद भी वहां पर कोई भी काम नहीं हुआ। स्पीकर

साहब, मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सिरसा जिले की तरफ भी ध्यान दे और आप इस बात को भूल जाएंगे कि उस जिले का नेता मुख्यमंत्री रह चुका है। इसलिए वहा पर काफी काम हुए होंगे। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि अगर किसान खुद ाहाल बनाना हैं तो उसको उस दलदल से निकलना होगा कि जिस दल दल में वे फसे हुए हैं। जैसे 20 मैम्बरो को एक परिवार है और 10 बीघे जमीन के टुकड़े पर अपना गुजार कैसे कर सकता है? वह इस दल दल से कैसे निकल सकता है और उसके परिवार का कैसे गुजारा हो सकता है? स्पीकर साहब, आज हरियाणा में कई ऐसे इलाके हैं, जहां पर ऐसे घर मौजूद हैं कि एक परिवार के 10 मैम्बर जमीन के बहुत छोटे से टुकड़े पर पैदावार करके गुजारा कर रहे हैं वे कहां जाए? वहां के लोग कहा जाए और किधर जायें? इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहां पर इण्डस्ट्रीज लगाने की जितनी भी गुजार्ई ा हो इण्डस्ट्रीज लगाई जानी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर सर। मेरी गुजारि ा यह है कि आज के बिजनैस में दो रैजयोलू ान हैं। अब इस समय पहले रैज्यूले ान पर डिस्क ान चल रही हैं। जो दूसरा रे रैज्यूले ान है वह भी इस प्रदे ा की जनता के राय लेकर आज सारा दिन हाउस को बैठाये रखें। आप कम से कम दो-चार घन्टे का समय अब य बढा ले। मैं विपक्ष

की तरफ से कहने को तैयार हूँ कि हाउस का समय बे ाक बढ़ा ले।

श्री अध्यक्ष: हाउस का समय डेढ़ बजे ता हैं। जब तक हाउस समय बढ़ाने के लिए सहमन न हो, उस समय तक मैं कैसे समय बढ़ा सकता हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप इन को समय बढ़ाने के लिए सहमत करा लिजिए वरना बहुत महत्वपूर्ण रैज्योलू ान रह जाएगा। इनक जो रैज्योलू ान चल रहा हैं उसको हम पास करवाने के लिए तैयार हैं। बे ाक ये इस को पास करवा लें।

श्री अध्यक्ष: समय बढ़ाने की बात मैं नहीं कह सकता जब तक सारा हाउस तैयार न हो।

श्री वीरेन्द्र सिंह: लीडर आफ दी हाउस को आप कह सकते हैं kindly extend the time of the House. ताकि दूसरा प्रस्ताव भी आ जाए।

श्री अध्यक्ष: मैं अपनी सैलफरिस्पैक्ट खोना नहीं चाहता क्योंकि अगर मैं उनको हाउस को समय बढ़ाने के लिए कहूंगा तो वे मानगे नहीं। इस बात का मुझे पता हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आपकी बात को सारे मैम्बर मानेंगे।

कृषि मंत्री(चौधरी सुरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, इस रैज्योलू न पर मिनिस्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि यह अन-ऑफिशियल है।

ठाकूर बहादूर सिंह: जो बातें मैंने कही हैं, उनके अन्दर वजन हैं और उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। जहाँ-जहाँ इण्डस्ट्री लगाए जाने की आवश्यकता हो वहाँ पर इण्डस्ट्री अवश्य लगाई जानी चाहिए। हमारा इलाका तरक्की करे, इस से सभी को खुशी होगी। सिरसा जिला भी हरियाणा प्रदेश का एक हिस्सा है।

Mr. Speaker: Please take your seat now. You will continue on next **Non Official day.**

अब हाउस कल दिनांक 11.03.1983 प्रातः 9.30 बजे तक के लिए एडर्जन किया जाता है।

***13.30 बजे**

(तत्पश्चात् सदन भुक्रवार, दिनांक 11.03.1983 प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ)

ANNEXURE

PAYMENT OF SALARIES OF THE PRIVATELY MANAGED COLLEGE TEACHERS

***26. Prof. Sampat Singh:** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) the number of privately managed colleges in the State where teachers have not been paid their salaries for more than two months;

(b) the steps, if any, taken to ensure regular payment of salaries to the teachers referred to in part (a) above?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा):

(क) 23 प्राइवेट कालेजों के अध्यापकों को फरवरी, 83 में दो मास से अधिक अवधि के लिए वेतन की अदायगी नहीं हुई थी।

(ख) सरकार प्राइवेट कालेजों के मान्य घाटे का 95 प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति करती हैं। जो अराजकीय महाविधालय वेतन अदायगी में देरी करते हैं उनके विरुद्ध हरियाणा अराजकीय महाविधालय (प्रबंधक अधिग्रहण) नियमावली, 1978 के तहत कार्यवाही की जाती है।